रीवा
17 सितम्बर 2025 बुधवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

रीवा, सतना एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

एशिया कप से...
@ पेज 7

युवराज सिंह-रॉबिन उथप्पा से ईडी पूछताछ करेगी

सट्टेबाजी एप के प्रचार का मामला; उर्वशी रोतैला को आज बुलाया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोटिस भेजा है। इन दोनों खिलाड़ियों से ऑनलाइन बेटिंग एप v&Bet के प्रमोशन मामले में पूछताछ की जाएगी। इसी मामले में आज बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रॉबिन उथप्पा को 22 और युवराज को 23 सितंबर को दिल्ली स्थित ED हेडक्वार्टर में अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को भी 24 सितंबर को पेश होने का समन भेजा गया है। इन सबसे मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से भी पूछताछ की जाएगी।

इसके अलावा सोमवार को इसी मामले में पूर्व टीएमसी सांसद और एक्टर मिमी चक्रवर्ती का बयान भी दर्ज किया है। श्च इस केस में शिखर धवन, सुरेश रैना और हरभजन सिंह से पहले ही पूछताछ कर चुकी है।

करोड़ों की ठगी और टैक्स चोरी की जांच यह जांच अवैध बेटिंग ऐप्स से जुड़ी है। कंपनी पर आरोप है कि उसने लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की है या बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की है।

असम की अफसर के घर मिले 2 करोड़ के जेवर,92 लाख कैश बरामद

असम सीएम बोले- रिश्वत लेकर हिंदुओं की जमीन संदिग्धों के नाम की

गुवाहाटी, एजेंसी। असम सिविल सेवा (ACS) की अधिकारी नूपुर बोरा को आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया। स्पेशल विजिलेंस टीम ने नूपुर के गुवाहाटी वाले घर पर छापा मारा। जहां से 92 लाख नकद और लगभग 2 करोड़ के जेवर बरामद किए गए।

एक दूसरी टीम ने बारपेटा में उनके किराए के घर पर भी छापा मारा, जहां से करीब 10 लाख नकद बरामद हुए।विजिलेंस ने नूपुर के सहयोगी लाट मंडल सुरजीत डेका के घर भी छापा मारा।

नूपुर पर आरोप हैं कि उन्होंने बारपेटा रेवेन्यू सर्किल में रहते हुए पैसे के बदले हिंदुओं की जमीन संदिग्ध व्यक्तियों के नाम की थी। फिलहाल नूपुर कामरूप के गोरोइमारी में सर्किल ऑफिसर हैं। सीएम सरमा ने कहा कि विवादित जमीन मामलों में नाम जुड़ने की शिकायतों के बाद पिछले 6 महीनों से उन पर नजर रखी जा रही थी। इसलिए हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

6 साल की सर्विस और आय से कहीं ज्यादा संपत्ति : असम सिविल सर्विस अधिकारी नूपुर बोरा 2019 में सिविल सेवा में शामिल हुईं। बोरा का जन्म 31 मार्च 1989 को हुआ था। वह कामरूप जिले के गोलाघाट की रहने वाली हैं।

देहरादून में बादल फटा, मंदिर, दुकानों-घरों में मलबा घुसा

टोंस नदी में ट्रैटर बहने से 8 लोगों के मरने की खबरः मंडी में 3 की मौत

शिमला, देहरादून,एजेंसी। उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार सुबह 5 बजे बादल फटा। इससे तमसा, कारलीगाड़, टोंस और सहस्त्रधारा नदी में जलस्तर बढ़ गया। सहस्त्रधारा समेत आसपास के इलाके तपोवन, आईटी पार्क, घंगौरा, घड़ी कैंट इलाकों में पानी भर गया। कई सड़कें बह गईं।

तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया। यहां मौजूद दुकानें बह गईं। 2 लोग लापता हैं। सहस्त्रधारा में 5 लोगों को बचाया गया। विकास नगर में टोंस नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। इस दौरान मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में बह गई। इसमें 8 लोगों की मौत और 4 के लापता होने की खबर है।

SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी ने बताया, सुबह 5 बजे नदी में बाढ़ आई, पूरा मंदिर डूब गया, कई मूर्तियां बह गईं। हालांकि, गर्भगृह

सुरक्षित है। पानी उतरने पर मंदिर में 2 फीट मलबा दिखा।

हिमाचल के धर्मपुर बस स्टैंड में मलबा भरा, मंडी में 3 की मौत : हिमाचल के मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड में भी रात में हुई बारिश के बाद मलबा भर गया। बाढ़ में कई बसें दूर तक बह गईं। राज्य में 3 नेशनल हाईवे बंद हैं। 493 सड़कों पर आवाजाही ठप है।मंडी के ही निहरी में लैंडस्लाइड के कारण 3 की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, पास की एक चट्टान का मलबा एक घर पर गिर गया, जिससे वह ढह गया। इसमें एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए।

सोमवार को भारी बारिश ने महाराष्ट्र के मुंबई में रेलवे ट्रैक, सब-वे और सड़कों पर पानी भर गया। बीड में 11 ग्रामीणों को वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया।

राहुल गांधी को गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाने पर विवाद

एसजीपीसी प्रधान बोले- कार्रवाई होगी, नोटिस जारी, कहा-यह सम्मान सिर्फ महापुरुषों के लिए

लुधियाना, एजेंसी। अमृतसर में 15 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें बाबा बुड्ढा साहिब जी के गुरुद्वारा साहिब और दरबार साहिब में प्रबंधकों ने सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया। सिरोपा देने के बाद विवाद खड़ा हो गया। विभिन्न सिख जत्थेबंदियों ने इस पर SGPC के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। मामले के SGPC के ध्यान में आने पर उन्होंने इस पर नोटिस लिया है।

सिख महापुरुषों को ही सिरोपा देने की अनुमति :SGPC ने मामले को लेकर बीती रात प्रेस नोट जारी किया। प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धामी ने बताया कि SGPC की अंतरिम

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी

गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा साहिब में हुई घटना की जांच जारी है। प्रधान एडवोकेट धामी ने कहा कि जल्द ही पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और यदि कोई दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
धामी ने यह भी कहा कि सिखों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता और गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी को गुरुद्वारा साहिब से सिरोपा देना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। यह सिख मर्यादा और परंपराओं के खिलाफ है।

कमेटी ने पहले ही फैसला किया था कि गुरुद्वारा साहिबान के दरबार में केवल धार्मिक हस्तियों, रागी सिंहों और सिख महापुरुषों को ही सिरोपा देने की अनुमति है। किसी अन्य विशेष व्यक्ति को यह सम्मान देने पर पाबंदी है।

राजस्थान की नदी का जहरीला पानी, मर रहे पशु-पक्षी,सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया

फैट्रियों का कचरा-केमिकल बहाया जा रहा, 20 लाख की आबादी प्रभावित

नई दिल्ली ,एजेंसी। राजस्थान की जोजरी नदी में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आसपास की फैक्ट्रियों से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधे नदी में गिराया जा रहा है। नतीजा, सैकड़ों गांवों का पानी दूषित हो गया है और लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। बता दें कि जोजरी नदी में प्रदूषण और जहरीले पानी के मामले को लेकर कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है।

सीजेआई के पास भेजा जाएगा मामला :जोजरी नदी में प्रदूषण और जहरीले पानी के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि मामला सीजेआई को भेजा जाए, ताकि आगे उचित आदेश दिए जा सकें। जोजरी नदी में औद्योगिक

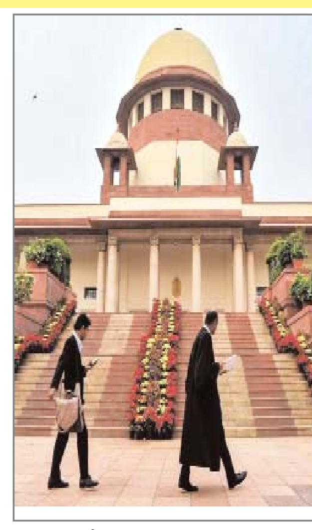

अपशिष्ट छोड़े जाने से स्वास्थ्य एवं अन्य पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को राजस्थान नदी प्रदूषण पर जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान वकील ने कहा- माननीय न्यायाधीश, मुझे सुबह बुलाया गया था, और मैं उपस्थित नहीं था। इसके बाद न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा- हमने रजिस्ट्री को राजस्थान नदी प्रदूषण से संबंधित एक जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश इस पर निर्णय लेंगे और उचित आदेश पारित करेंगे।

लोगों और पशुओं के पीने योग्य नहीं बचा पानी- कोर्ट

PTI के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा- ''यह अदालत राजस्थान की मरुधरा जोजरी नदी में छोड़े जा रहे औद्योगिक अपशिष्ट के संबंध में स्वतः संज्ञान ले रही है, जहां मुख्यतः वस्त्र और टाइल्स कारखानों से भारी मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ा जा रहा है, जिससे सैकड़ों गांवों में रहने वाले लोगों और पशुओं के लिए जल पीने योग्य नहीं रह गया है।''

जानें जोजरी नदी के बारे में :आपतो बता दें कि जोजरी नदी राजस्थान के नागौर जिले के पोंडलू गांव के समीप से निकलती है। जानकारी के मुताबिक, जोजरी नदी की लंबाई करीब 83 किलोमीटर है और जोधपुर और बाड़मेर जिलों से होकर बहते हुए लूनी नदी में मिल जाती है।

फैसले के खिलाफ हर कोई अपील नहीं कर सकता, मालेगांव मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी

मुंबई, एजेंसी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ किया है कि किसी आरोपी की बरी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। अदालत ने कहा कि यह कोई खुला दरवाजा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपील लेकर पहुंच जाए। हाईकोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि मृतकों के परिजनों को ट्रायल के दौरान गवाह बनाया गया था या नहीं। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकड़ की खंडपीठ ने की। अदालत छह पीड़ितों के परिजनों द्वारा दायर अपील सुन रही थी, जिसमें विशेष एनआईए अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सात आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इन आरोपियों में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल थे।

परिजनों के गवाह बनने पर सवाल :सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या पीड़ित परिवारों के सदस्य गवाह थे। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि पहले अपीलकर्ता निसार अहमद, जिनके

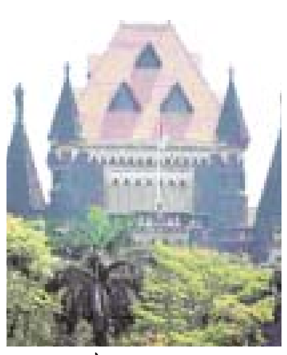

बेटे की मौत धमाके में हुई थी, ट्रायल में गवाह नहीं बने थे। इस पर अदालत ने कहा कि अगर बेटे की मौत हुई थी तो पिता को गवाह होना चाहिए था। अदालत ने आदेश दिया कि इस बारे में पूरी जानकारी बुधवार को दी जाए।

अपीलकर्ताओं का तर्क :परिजनों की ओर से दाखिल अपील में कहा गया है कि जांच में खामियां होना या जांच एजेंसियों की गलती होना बरी करने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि ब्लास्ट की साजिश गुप्त तरीके से रची गई थी, इसलिए उसका सीधा सबूत मिलना संभव नहीं था। अपील में यह भी कहा गया कि 31 जुलाई को एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दिया गया फैसला गलत और कानून के खिलाफ था, जिसे रद्द किया जाना चाहिए।

2008 का धमाका और नुकसान :29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव कस्बे में एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में बंधा विस्फोटक धमाका कर गया था। इस धमाके में छह लोगों की मौत हुई और 101 लोग घायल हुए थे। घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया था। उस समय एटीएस ने मामले की जांच कर सात लोगों को गिरफ्तार किया था और एक बड़े आतंकी साजिश का खुलासा किया था।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसलाः महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी, 2026 तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने महाराष्ट्र के अधिकारियों को इस साल 10 अक्तूबर तक राज्य में परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि 6 मई को जारी उसके तर्कसंगत आदेश के बावजूद राज्य चुनाव आयोग इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने में विफल रहा। तत्कालीन आदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना चार सप्ताह के भीतर और चुनाव चार महीने के भीतर कराने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने अब महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हुए समय सीमा में और विस्तार दे दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

2022 में यथास्थिति बनाए रखने का दिया था निर्देश :इससे पहले 22 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार को स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

चुनाव आयोग को दी थी चेतावनी

शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई 2022 को राज्य चुनाव आयोग को चेतावनी दी थी कि अगर उसने स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया को फिर से अधिसूचित किया तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला अध्यादेश लेकर आई थी।

महिला का स्तन दबाने वाला हांडीखेड़ा बाबा विवादों में

● सिरसा में कबाड़ी-हेयर ड्रेसर रहा, फिर झाड़-फूंक करने लगा; बाउंसर भी रखे

सिरसा, एजेंसी। हरियाणा में सिरसा जिले के हांडीखेड़ा गांव में दरबार लगाकर झाड़-फूंक करने वाले बाबा संजय भगत की ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत दी है। इसमें आरोप है कि बाबा के द्वारा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। झाड़ा लगाने के नाम पर सरसों का तेल और हजारों रुपए लिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले राजस्थान के मेहंदीपुर के एक व्यक्ति ने भी बाबा के खिलाफ शिकायत दी, जिसमें कहा कि बाबा ने उपाय बताने के लिए पैसे लिए, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। पुलिस बाबा को थाने ले गई। हालांकि, बाद में छोड़ दिया।

सदर थाना प्रभारी सुखबीर सिंह ने बताया कि मेहंदीपुर के युवक ने पहले शिकायत दी थी। बाबा को थाने लाया गया। बाद में

शायद बाबा से पैसे वापस मिल गए या समझौता हो गया तो शिकायत वापस ले ली। ग्रामीणों ने एक बार पहले शिकायत दी थी, फिर वापस ले ली थी। अब ग्रामीणों की दूसरी शिकायत आई हुई है, इसकी जांच करवाएंगे।

बाबा अपने दरबार में लोगों की बीमारियों ठीक करने और नशा छुड़ाने का दावा करता है। गांव में विरोध शुरू होने के बाद उसने बाउंसर तक रख लिए हैं। बाबा बनने से पहले वह हेयर ड्रेसर से लेकर कबाड़ी तक का काम कर चुका है। बाबा ज्यादा विवादों में तब आया, जब झाड़ा लगाने के नाम पर वह महिला के छाती दबाते हुए नजर आया।

राजस्थान-कांग्रेस की महिला विधायक बोलीं-स्पीकर हमारी निजी बातें सुनते हैं,महिलाएं सदन तक में सुरक्षित नहीं

प्राइवेसी या बेडरूम-बाथरूम तक ही रहेगी

जयपुर,एजेंसी। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की तरफ एक्स्ट्रा कैमरे लगाने के मामले में सियासी विवाद जारी है। अब कांग्रेस की महिला विधायकों ने स्पीकर पर सवाल उठाए हैं।

अनूपगढ़ से कांग्रेस विधायक शिमला नायक और भोपालगढ़ से विधायक गीता बरवड़ ने कहा- सदन में पहले से 9 कैमरे थे, लेकिन दो जासूसी कैमरों से स्पीकर और मंत्री हमारी रिकॉर्डिंग देखते हैं। हमारी निजी बातें सुनते हैं। दोनों जासूसी कैमरों से हमारी निजता का हनन हो रहा है।

दोनों महिला विधायक सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रही थीं। शिमला नायक ने कहा- विधानसभा सदन में अगर एक पेन भी गिरता है तो उसकी आवाज भी दोनों जासूसी कैमरे

रिकॉर्ड करते हैं। इन जासूसी कैमरों का एक्सेस स्पीकर के रेस्ट रूम में है। यहां पर स्पीकर के साथ मंत्री और बीजेपी विधायक हमारी बातचीत सुनते और हमें देखते हैं।

जासूसी कैमरे हमारे कागज पर लिखा ब्योरा तक कैद करते हैं : नायक ने कहा- विधानसभा सत्र के दौरान हम रणनीति बनाते हैं। आपसी बातचीत करते हैं या किसी पर्सनल मैटर पर बात करते हैं तो ये हाई रेजोल्यूशन वाले जासूसी कैमरे हमारी बातें तो रिकॉर्ड करते ही हैं, साथ ही हमारे पास कागज पर लिखा हुआ ब्योरा भी कैद कर लेते हैं। पेन गिरने की आवाज तक ये जासूसी कैमरे रिकॉर्ड करते हैं। कांग्रेस की सभी महिला विधायकों ने इस पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। आपको ऐसा करने का अधिकार किसने दिया?

कैमरे की हार्ड डिस्क दिखाई जाए, क्या रिकॉर्ड हो रहा है?

शिमला नायक ने कहा- विधानसभा सदन में दो जासूसी कैमरों को किसकी मंजूरी से लगाया है? जासूसी कैमरों की हार्ड डिस्क दिखाई जाए कि इसमें क्या-क्या रिकॉर्ड हो रहा है? इन दो कैमरों के जरिए हमारी निजी बात सुनने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को किसने दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बिना अनुमति किसी की निजी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है।

बाढ़ से सबक...दिल्ली में यमुना नदी के डूब क्षेत्र में इतने एकड़ जमीन सुरक्षित

नई दिल्ली,एजेंसी। राजधानी में यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र से 2012.99 एकड़ जमीन (814.631 हेक्टेयर) को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इसमें जोन-0 में भूमि प्रबंधन विभाग ने 2.22 एकड़ और बागवानी विभाग की तरफ से 2010.78 एकड़ जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। यह कार्रवाई 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2025 के दौरान की गई है। इसके अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने विभाग को ब्योरा दिया है कि उन्होंने जोन-ह का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और अब अधिकारी निष्कर्षों के आधार पर अतिक्रमण का विश्लेषण कर रहे हैं।

एनजीटी ने दिल्ली सरकार, डीडीए और अन्य एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वजीराबाद से पल्ला तक 22 किमी लंबे यमुना के बाढ़ प्रभावित इलाके का सीमांकन कर अवैध निर्माण हटाया जाए। इसके तहत नवंबर, 2023 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसको लेकर अब तक छह बार स्थिति रिपोर्ट दायर की गई हैं। यह कार्रवाई उस समय शुरू हुई जब एनजीटी ने 22 अगस्त, 2023 को एक मीडिया रिपोर्ट 'बाढ़ ने डीडीए के मास्टर प्लान पर पुनर्विचार क्यों किया' का स्वतः संज्ञान लिया था। रिपोर्ट में यमुना के बाढ़ क्षेत्र में हो रहे अनधिकृत निर्माण से राजधानी में आई बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताई गई।

यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में इतना अतिक्रमण

डीडीए की तरफ से किए गए हालिया सर्वे अगस्त 2024 के अनुसार, यमुना नदी का बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन) कुल 9,700 हेक्टेयर में फैला हुआ है जो दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत जोन-ह के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र वजीराबाद से पल्ला तक लगभग 22 किलोमीटर

लंबी पट्टी को कवर करता है। इस क्षेत्र का लगभग 75 फीसदी हिस्सा (7,362.56 हेक्टेयर) अवैध अतिक्रमण के अधीन है। इसमें अनधिकृत कॉलोनियां, झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) क्लस्टर, परिवहन परियोजनाएं और अन्य निर्माण कार्य हैं।

सीमांकन में आई तकनीकी दिक्कतें: रिपोर्ट के अनुसार, अदालत के 30 अप्रैल 2025 के आदेश के अनुसार डीडीए के वकील ने जवाब दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि सीमांकन के दौरान तकनीकी विसंगतियां सामने आईं। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर 1:25 वर्ष की बाढ़ सीमा और 1:100 वर्ष की बाढ़ सीमा में विरोधाभास है। इससे सर्वे प्रभावित हुआ। इस मुद्दे को हल करने के लिए दिल्ली के कई विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं। ऐसे में अदालत ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण प्रमुख सचिव को निर्देश दिया था कि वे सभी संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक करें और मानचित्र में मिली विसंगतियों को दूर करें। यह काम चार सप्ताह की अवधि के अंदर पूरा करें।

सीमा का विश्लेषण कर नक्शा तैयार किया

रिपोर्ट में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएफसीडी) का भी हवाला दिया गया है। इसमें अधिकारियों ने बताया है कि हाल की बाढ़ के बाद यमुना के बाढ़ क्षेत्र का वैज्ञानिक आकलन कराने के लिए 80 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। जीएसडीएल द्वारा बाढ़ सीमा का विश्लेषण कर नक्शा तैयार किया गया जिसे डीडीए को सीमांकन के लिए सौंपा गया है। डीडीए 1 सितंबर 2025 से सीमांकन शुरू करेगा और बोलार्ड लगाने की समय-सीमा भी तय करेगा।

डीडीए ने किया था यमुना के बाढ़ क्षेत्र का सर्वे: दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर डीडीए ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र का सर्वे किया था। इस सर्वे में सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया गया था। सर्वे में पाया गया कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र की 7,362 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है और यहां बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण भी हुआ है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में इस जमीन को जोन-ह के नाम से जाना जाता है। हाई लेवल कमेटी के निर्देश पर डीडीए ने यमुना के किनारे की जमीन का ग्राउंड-ट्रूथिंग सर्वे भी किया।

चुनाव प्रचार अंतिम दौर में, उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत; कॉलेजों में जाकर मांगा समर्थन

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के उम्मीदवारों ने नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के

कॉलेजों में प्रचार किया। चुनाव के लिए एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर आर्यन मान, उपाध्यक्ष पद पर गोविंद तंवर, सचिव पद पर कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा को मैदान में उतारा है। एबीवीपी से डूसू अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान ने कहा कि कैंपस परिसरों में छात्रों का अथाह प्यार मिल रहा है। पूर्व में एबीवीपी-नीत डूसू पदाधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों को लेकर हम छात्रों के बीच जा रहे हैं। चाहे यू-स्पेशल बस की शुरुआत हो या कॉलेज में आईसीसी का सुचारू संचालन हो। ऐसे तमाम मुद्दों पर छात्र हमारे साथ खड़े हैं। पूर्ण विश्वास है कि आगामी छात्रसंघ चुनाव में छात्र एबीवीपी पर भरोसा जताएंगे और हमारी जीत सुनिश्चित करेंगे। एबीवीपी से उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार गोविंद तंवर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो वर्ष के 365 दिन छात्रहितों की बात करता है। यही एबीवीपी को अन्य संगठनों से अलग करता है। इस वर्ष एबीवीपी यूनिवर्सिटी हेल्थ कार्ड, ओपन जिम, सब्सिडाइज्ड स्वास्थ्य बीमा और जॉब मेला जैसे विषयों पर कार्य करने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एबीवीपी के पक्ष में जनमत आएगा और केंद्रीय पैनल की सभी सीटों पर एबीवीपी विजय प्राप्त होगी। एबीवीपी से सचिव पद के उम्मीदवार कुणाल चौधरी ने कहा एबीवीपी की विशेषता है कि यह पूरे वर्ष जमीन पर सक्रिय रहती है, केवल रील पर नहीं। इस वर्ष एबीवीपी विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट, 10 हजार से अधिक इंटर्नशिप, मुफ्त एआई टूल्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और चतुर्थ वर्ष के छात्रों के लिए रिसर्च पेपर लेखन में सुविधा जैसे मुद्दों पर कार्य करेगी। मुझे विश्वास है कि इस बार हमारा पैनल भारी मतों से विजयी होगा और डीयू के इतिहास में नया अध्याय लिखेगा। एबीवीपी से संयुक्त सचिव पद की उम्मीदवार दीपिका झा ने कहा कि सभी कॉलेजों में छात्राओं का स्नेह और समर्थन मिल रहा है।

एनएसयूआई के लिए सचिन पायलट ने मांगे वोट, बोले-जीत से बदलेगा डीयू: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एनएसयूआई के समर्थन में अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को मिरांडा कॉलेज, कैंपस लॉ सेंटर और हिंदू कॉलेज में छात्रों से एनएसयूआई पैनल को समर्थन देने की अपील की। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि एनएसयूआई डूसू चुनाव में जीत दर्ज करके दिल्ली विश्वविद्यालय को बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने दावा किया कि एनएसयूआई ने संतुलित और साफ-सुथरी छवि वाला पैनल उतारा है, जिसे छात्रों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में बेरोजगारी, शिक्षा का निजीकरण और फीस वृद्धि जैसी समस्याओं के लिए भाजपा की सरकारें जिम्मेदार हैं। वहीं भाजपा सरकार ने तो नए कॉलेज खोले, न ही सीटें बढ़ाईं। लिहाजा डूसू चुनाव में युवाओं की आवाज बैलेट पर साफ सुनाई देंगी। देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र राजनीति का प्रमुख केंद्र है, जिसने देश को बड़े नेता दिए हैं। एनएसयूआई केवल संगठन नहीं, बल्कि छात्रों के लिए अपने भविष्य की दिशा तय करने का पहला पड़ाव है। यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जिस तरह सत्ता पर काबिज हो रही है, उससे नाराज छात्र एबीवीपी का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले डूसू चुनाव में एनएसयूआई अध्यक्ष और सहसचिव पद पर जीती थी, लेकिन इस बार चारों पदों पर जीत सुनिश्चित है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी एनएसयूआई पैनल के समर्थन में बैठक हुई, जिसमें दिल्ली प्रभारी निजामुद्दीन काजी और पूर्व मंत्री डॉ. नरेन्द्र नाथ समेत कई नेताओं ने भाग लिया।

नेपाल में प्रदर्शन के दौरान मारे गए 10 छात्रों का अंतिम संस्कार किया गया

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में 8 और 9 सितंबर के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान अपनी जान गंवाने वाले दस छात्रों का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया गया है। इनमें से नौ शवों को महाराजगंज के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में और एक को पाटन अस्पताल में रखा गया था। नेपाल की अंतरिम सरकार ने एक दिन पहले सोमवार को जेन-जी आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों को आधिकारिक तौर पर शहीदों का दर्जा देने का फैसला लिया था। सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और सार्वजनिक अवकाश दिया है। मृत छात्रों के बलिदान का सम्मान करने के लिए आज अंतिम संस्कार जुलूस निकाला गया, जिसकी शुरुआत शिक्षण अस्पताल से हुई और दाह संस्कार से पहले रिंग रोड पर इस शव यात्रा को घुमाया गया। त्रिभुवन विश्वविद्यालय की प्रवक्ता काली प्रसाद रोज्यारा के अनुसार काठमांडू के बाहर रहने वाले मृतकों के शवों को उनके गंतव्य तक भेज दिया गया है। आज काठमांडू के 10 मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है।

एम्स से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में होगी महिलाओं की स्क्रीनिंग

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से शुरू होने वाले स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के तहत एम्स से लेकर 69 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर स्क्रीनिंग होगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में यह अभियान 17 सितंबर से लेकर दो अक्तूबर तक चलेगा। एम्स दिल्ली की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. निरुपम मदान ने कहा कि उस दिन मुख्य एम्स, त्रिलोकपुरी केंद्र, बल्लभगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और झज्जर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं।

यह शिविर विशेष तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की स्क्रीनिंग के लिए आयोजित किए जाएंगे। इसमें सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, आंखों की जांच सहित संचारी और गैर संचारी बीमारियों की जांच की जाएगी। बच्चे भी स्क्रीनिंग के लिए आ सकते हैं। साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा।

यह गतिविधियां पूरे पखवाड़े तक चलेगी। सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक महिलाओं के लिए वॉक इन रहेगा। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आयोजित होने वाले विशेष स्वास्थ्य शिविरों में महिलाओं के ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, टीबी की जांच, ईएनटी से संबंधित बीमारियों व आंखों की स्क्रीनिंग की जाएगी। शाहदरा जिले के गांधी नगर इलाके में साल साल की मासूम के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोप है कि रिश्तेदार वारदात के बाद मासूम को छोड़कर फरार हो गया। बाद में उसके अस्पताल में भर्ती होने का पता चला। मासूम की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मासूम की काउंसलिंग कराई गई है। पुलिस ने यौन शोषण के अलावा पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही आरोपी को अस्पताल से छुट्टी मिलेगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल उसकी निगरानी की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक गांधी नगर निवासी मासूम के पिता प्राइवेट जॉब करते हैं। पुलिस को दिए बयान में मासूम की मां ने बताया कि 12 सितंबर की रात 9 बजे उनके दोनों बच्चे गली में खेल रहे थे। वह अपनी जेठानी के साथ सब्जी लेने मार्केट जा रही थीं। इस बीच इलाके में ही रहने वाला उनका एक रिश्तेदार बेटी का हाथ पकड़कर उनके पास लाया।

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले काली मंदिर पर धावा, मूर्तियां तोड़ीं

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में नवरात्रि और दुर्गा पूजा से पहले एक हिन्दू मंदिर पर की गई तोड़फोड़ से अल्पसंख्यक समुदाय भयभीत है। बताया गया है कि रविवार रात कुश्तिया के मीरपुर उप जिला स्थित स्वरूपदाह पालपारा रक्खा काली मंदिर में बदमाशों ने दो मूर्तियों को खंडित कर दिया। बदमाश तोड़फोड़ करने के बाद एक सीसीटीवी और एक मेमोरी कार्ड अपने साथ ले गए। द डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, मीरपुर थाना प्रभारी मोमिनुल इस्लाम ने बताया कि घटना रविवार रात 8:00 बजे से 8:30 बजे के बीच हुई होगी। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही कोई शिकायत दर्ज की गई है। घटना की जांच की जा रही है।

मंदिर समिति के पूर्व सचिव बादल कुमार डे ने कहा कि हम लोग पिछले तीन साल से यहां दुर्गा पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। दुर्गा पूजा से पहले हुई इस घटना से सभी लोग दहशत में। उन्होंने कहा कि बदमाशों ने मंदिर का सुरक्षा कैमरा और उसका मेमोरी कार्ड लूट लिया। कुश्तिया के उपायुक्त अबू हसनत मोहम्मद अराफिन ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मंदिर में मौजूदा सुरक्षा उपायों के बारे में पूछे जाने पर अराफिन ने कहा कि नए कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा, अंसार के सदस्य चौबीसों घंटे तैनात रहते हैं।

आईटीओ बैराज दिल्ली सरकार को सौंपने पर हरियाणा सहमत

2023 की बाढ़ से सबक लेकर फैसला

नई दिल्ली ,एजेंसी। हरियाणा सरकार ने यमुना नदी पर स्थित आईटीओ बैराज को दिल्ली सरकार के नियंत्रण में सौंपने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली में बाढ़ से निपटने में आसानी होगी। 2023 में दिल्ली में आई बाढ़ के लिए बैराज के खराब गेट बड़ी वजह बने थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इसके नियंत्रण की मांग की थी।

दिल्ली सरकार के अनुरोध के बाद हरियाणा सरकार ने आईटीओ बैराज को सौंपने का निर्णय लिया है। इस बार मानसून से पहले ही बैराज के सभी 32 गेटों की मरम्मत कर दी गई थी, ताकि 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति

दोबारा न हो।

दिल्ली में यमुना नदी पर तीन बैराज हैं, जिनमें से केवल वजीराबाद बैराज ही दिल्ली सरकार के पास है। ओखला बैराज, उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है, जबकि आईटीओ बैराज अब तक हरियाणा के पास था। यह बैराज नई दिल्ली के बिल्कुल करीब है, जिसके कारण इसका प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है।

पहले भी लिखा था पत्र

दिल्ली सरकार ने पहले भी इसके लिए हरियाणा को पत्र लिखा था, पर अब दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होने का फायदा मिला है। दिल्ली के अधिकारियों का कहना है कि नियंत्रण मिलने से न केवल बैराज के गेटों का रखरखाव बेहतर होगा, बल्कि बाढ़ से निपटने की तैयारी भी मजबूत होगी।

दिल्ली में जन्म दर घटी, शिशु और मातृ मृत्यु दर में सुधार

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली में जन्म दर घट गई है जबकि मृत्यु दर बढ़ गई है लेकिन शिशु और मातृ मृत्यु दर में सुधार हुआ है। ज्यादातर शिशुओं के जन्म अस्पतालों में हो रहे हैं। 2024 की जन्म और मृत्यु पंजीकरण की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि लोगों का दिल्ली की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 14 रही है, जो कि 2023 की दर 14.66 से कम है। मृत्यु दर 6.37 रही, जो पिछले साल के 6.16 से ज्यादा है लेकिन अच्छी खबर यह है।

ऑपरेशन सिंदूर में टुकड़े-टुकड़े हुआ मसूद अजहर का परिवार, जैश कमांडर ने भरे मंच से कबूला

इस्लामाबाद ,एजेंसी। ऑपरेशन सिंदूर के कई महीने बाद अब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने भी स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में हुए हमले में खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े-टुकड़े हो गए थे। जैश ए मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जैश कमांडर मसूद इलियास ने क्या कहा: इस वीडियो में मसूद इलियास कश्मीरी ने बताया कि किस तरह से भारतीय सशस्त्र बलों ने उनके ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया। वीडियो में मसूद इलियास कहते हुए सुनाई दे रहा है कि अपने देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए हम दिल्ली में लड़े, काबुल और कांधार में लड़े। सबकुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को मौलाना मसूद अजहर के परिवार को तबाह कर दिया गया। भारतीय सुरक्षा बलों ने बहावलपुर में उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर दिया।

ऑपरेशन सिंदूर : जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम तरीके से हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भी बाद में स्वीकार किया कि नौ जगहों पर हमला हुआ। इनमें बहावलपुर, कोटली और मुरीदके जैसे आतंकी प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल थे। बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है ।

बलोचिस्तान में आईईडी विस्फोट में कैप्टन समेत पांच सैनिक मारे गए

इस्लामाबाद (पाकिस्तान), एजेंसी। पाकिस्तान के बलोचिस्तान के केच जिले में सुरक्षा बलों पर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से किए गए हमले में एक कैप्टन समेत पांच सैनिक मारे गए। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने सोमवार देररात बताया कि दोपहर के वक्त केच के शेर बांदी में सैनिकों की टुकड़ी के आगे बढ़ने पर आईईडी विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में एक कैप्टन समेत देश के पांच बहादुर सपूतों की जान चली गई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद सुरक्षा बलों ने पांच आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए सैनिकों में लोरलाई के 25 वर्षीय कैप्टन वकार अहमद, डेरा गाजी खान के 35 वर्षीय

नायक असमत उल्लाह, सुक्कुर के 29 वर्षीय लांस नायक जुनैद अहमद, मर्दन के 29 वर्षीय लांस नायक खान मोहम्मद और स्वाबी के 28 वर्षीय सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल हैं। आईएसपीआर ने कहा, ÷हमारे बहादुर अधिकारियों और सैनिकों की शहादत हमारे संकल्प को और मजबूत करती है।÷ उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल ÷देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर दृढ़ हैं। इससे पहले, 13 और 14 सितंबर को खैबर-पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने एक अभियान में 31 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। 19 सैनिक मारे गए। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 45 आतंकवादी मार गिराए।

चार्ली की मौत का जश्न मनाने वालों का रद्द करेंगे वीजा, निर्वासन के लिए तैयार रहें, रूबियो की चेतावनी

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ऐसे विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द किए जा रहे हैं, जो दक्षिणपंथी टिप्पणीकार चार्ली किर्क की हत्या पर जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका उन विदेशियों को अपने देश में नहीं रखेगा जो हमारे नागरिकों की मौत का जश्न मनाते हैं। फॉक्स न्यूज से बातचीत में रूबियो ने कहा कि अमेरिका को ऐसे लोगों को देश में घुसने या रहने की अनुमति नहीं मिलनी

चाहिए, जो इस तरह की हत्याओं का समर्थन करते हैं या उनका जश्न मनाते हैं। उन्होंने कहा, हमें ऐसे लोगों को वीजा नहीं देना चाहिए जो अमेरिका आकर किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या, फांसी या हत्या जैसी घटनाओं का जश्न मनाएं और अगर वो पहले से यहां हैं, तो उनका वीजा रद्द कर देना चाहिए।

रूबियो ने एक्स पर अपने बयान का वीडियो साझा किया और लिखा, जो लोग हमारे नागरिकों की मौत का जश्न मना रहे हैं, उन्हें अमेरिका में जगह नहीं मिलेगी। वीजा रद्द किए जा रहे हैं। अगर आप वीजा पर यहां हैं और किसी राजनीतिक व्यक्ति की सार्वजनिक हत्या पर खुश हो रहे हैं, तो निर्वासन के लिए तैयार हो जाइए। इस देश में आपका स्वागत नहीं है।

सीनेट की समिति के सामने पेश होंगे एफबीआई प्रमुख, चार्ली की हत्या की जांच सहित इन सवालों का करना होगा सामना

वॉशिंगटन, एजेंसी। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निदेशक काश पटेल को सीनेट की एक समिति की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद उनसे चार्ली किर्क की हत्या की जांच और एफबीआई के अंदर वरिष्ठ अधिकारियों को हटाए जाने को लेकर कड़े सवाल पूछ सकते हैं। इन अधिकारियों ने एफबीआई निदेशक पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।

सीनेट की न्यायपालिका समिति उनसे पूछताछ करेगी। एफबीआई प्रमुख के पद पटेल को अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों भरा रहा है। समिति के सामने पटेल को

साबित करना होगा कि एफबीआई के अंदरूनी उथल-पुथल और अमेरिकी में बढ़ती राजनीतिक हिंसा के बीच वह पद के लिए सही व्यक्ति हैं।

पटेल का अब तक का विवादों भरा कार्यकाल : पटेल इससे पहले जनवरी में समिति के समक्ष पेश हुए थे, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों को आश्वासन दिया था कि वह निदेशक के रूप में किसी भी तरह की राजनीतिक बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। अब उन्होंने पूछा जाएगा कि क्या उन्होंने ऐसा किया है। एफबीआई ने पिछले महीने पांच एजेंटों और वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त किया है। मौजूदा व पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इससे विभाग का मनोबल गिरा है और असंतोष फैला है। पटेल को इससे जुड़े सवालों का जवाब देना होगा।

अधिकारियों ने अदालत में दायर किया है मुकदमा : इनमें से तीन अधिकारियों ने पिछले हफ्ते एक संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पटेल को पता था कि इन अधिकारियों की बर्खास्तगी को अवैध घोषित किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए इन्हें अंजाम दिया। इन अधिकारियों में से एक ने छह जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में हुए दंगों की जांच में अहम भूमिका निभाई थी और एक अन्य अधिकारी काकार्यवाहक निदेशक रहते हुए न्याय विभाग के अधिकारियों से टकराव हुआ था। एफबीआई ने इस मामले पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपब्लिकन सांसद कर सकते पटेल का बचाव सीनेट की इस समिति में रिपब्लिकन पार्टी के सांसद बहुमत में हैं। वह पटेल का समर्थन कर सकते हैं।

शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली में 'विश्व ओजोन दिवस' का आयोजन

मानव जीवन के अस्तित्व के लिए ओजोन परत आवश्यक : प्रोफेसर सुनील सिंह

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशों के अनुपालन तथा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. गीता भारती के मार्गदर्शन में, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के त्रैमासिक कैलेंडर के अनुसार मंगलवार 16 सितंबर को शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली में ''विश्व ओजोन दिवस'' का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित भविष्य – सुरक्षित पृथ्वी के संदेश को जन–जन तक पहुँचाना और ओजोन परत की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई।

मुख्य वक्ता प्रो. सुनील सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ओजोन परत मानव जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए ढाल का कार्य करती है। इसमें छिद्र होने से हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुँचती हैं, जिससे त्वचा रोग, कैंसर और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। उन्होंने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने पर विशेष जोर दिया। डॉ. वाहिदुन निशा ने अपने उद्बोधन में कहा कि यदि ओजोन परत सुरक्षित नहीं रही, तो मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु–पक्षी, वनस्पतियाँ और संपूर्ण जैवमंडल संकट में आ जाएगा। डॉ. सुरेश तिवारी ने ओजोन परत के क्षरण से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी खतरों, विशेषकर त्वचा कैंसर और जैव विविधता को होने वाले नुकसान पर प्रकाश डाला।

डॉ. भावना नागेंद्र ने सतत जीवनशैली अपनाने की अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकार या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है। यदि हम सामूहिक रूप से प्रयास करें तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण दे सकते हैं।

कार्यक्रम में प्रो. बी.एल. सिंह आयाम, प्रो. राजकिशोर तिवारी, डॉ. असलेंद्र जायसवाल, डॉ. रेनू सिंह, सुषमा शुक्ला, डॉ. पंकज सिंघल, मनीष कुमार सोनी, सिद्धनाथ केवट सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे और वक्ताओं के साथ संवाद कर ओजोन परत की सुरक्षा के महत्व को गहराई से समझा। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के समन्वयक डॉ. संदीप कुमार शर्मा और डॉ. गंगा देवी बैरागी ने कार्यक्रम का सफल संचालन और संयोजन किया। अंत में सभी उपस्थित अतिथियों, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया गया।

लैंड पूलिंग एक्ट स्थगित कर पुरानी व्यवस्था ही लागू रखें : अजय सिंह

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश भर में गहराते खाद संकट को लेकर किसानों के गुस्से को रोकने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सब काम छोड़कर केवल किसानों की समस्या को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अजय सिंह ने लैंड पूलिंग एक्ट को स्थगित कर पुरानी व्यवस्था बहाल रखने का आग्रह भी किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि अफसरों की न मानते हुए किसानों की सुनें और उनसे बातचीत कर हल निकालें, अन्यथा किसानों का गुस्सा फूटने पर संभालना मुश्किल हो जाएगा।

अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश भर से खाद की किल्लत को लेकर किसानों के हलाकान होने की खबरें तेजी से आ रही हैं। खाद के लिए टोकन लेने में भी परेशानी हो रही है। टोकन लेने के लिए लंबी–लंबी लाइनें लगी हैं। जैसे–तैसे किसान टोकन ले भी लेता है, तो उसे खाद नहीं मिलती। यदि खाद मिल भी जाती है, तो उसके नकली निकलने की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कृषि मंत्री के संसदीय क्षेत्र से भी शिकायतें मिल रही हैं। जांच के लिए समिति बनाकर प्रशासन ने इतिश्री कर ली है। नकली खाद बाजार में आ ही क्यों रही है? अफसर कहते हैं कि खाद का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन फिर भी बंटवारे में कमी क्यों है?

सिंह ने कहा कि सरकार बिलकुल समझ नहीं रही है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। खाद की कमी और समय पर न मिलने के कारण फसल की गुणवत्ता खराब हो रही है, जिससे उत्पादन कम होगा और किसानों की आय घटेगी। अजय सिंह ने कहा कि किसान खाद संकट से जूझ रहा है और ऊपर से लैंड पूलिंग एक्ट लाद दिया गया है। पहले धार्मिक आयोजनों के समय अस्थायी निर्माण के लिए किसानों से जमीन ली जाती थी, जिसका मुआवजा मिलता था और बाद में जमीन वापस मिलती थी। लेकिन अब लैंड पूलिंग एक्ट आने के बाद किसान की जमीन हमेशा के लिए ले ली जाएगी। इस कानून को लाकर सरकार किन बड़े लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है, यह जनता के बीच स्पष्ट होना चाहिए।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 186 आवेदकों की समस्याएं, निराकरण के दिए निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक नियमित रूप से जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। आज आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने जिले के विभिन्न अंचलों से आए 186 आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना।

कलेक्टर ने आवेदनों की सुनवाई के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियों से मौके पर ही जानकारी प्राप्त की और तत्काल निराकरण योग्य समस्याओं को तुरंत निराकृत करने के निर्देश दिए। वहीं जिन प्रकरणों के समाधान में समय लगेगा, उनके लिए निर्धारित समय–सीमा तय कर अधिकारियों को अनिवार्य रूप से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सोमवंशी ने कहा कि शासन की मंशा है कि हर नागरिक को उसकी समस्या का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान उपलब्ध हो। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जनसुनवाई के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमन राज, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास राकेश शुक्ला, सिहावल प्रिया पाठक, मझौली आरपी त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी सहित जिला स्तरीय अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर ने विभागवार लंबित मामलों की भी जानकारी ली और अधिकारियों को जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर बल दिया।

आज की जनसुनवाई में तहसीलदारों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की, जिससे जिले के दूरस्थ अंचलों की समस्याओं को भी सीधे जिला स्तरीय मंच पर प्रस्तुत किया जा सका। इस व्यवस्था से जनसुनवाई और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बन गई।

व्यापारी महासंघ ने आयोजित किया बंगाल फाइल्स का स्पेशल शो

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। 15 सितंबर शाम 7:30 बजे समदड़िया गोल्ड, सिरमौर चौराहा में बंगाल फाइल्स फिल्म का स्पेशल शो आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की पुष्प आरती और तिरंगे झंडे को लहराकर भारत माता की जय घोष के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जनार्दन मिश्रा, सांसद लोकसभा क्षेत्र रीवा, वीरेंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राजीव तिवारी, निज सचिव उपमुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष अतुल जैन, स्वामी हंसदास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी, और अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

जोड़ों के दर्द में फिजियोथेरेपी के साथ पीआरपी दे रही बेहतर आराम : डॉ. आकाश सावजी

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। हर वर्ष 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को फिजियोथेरेपी और व्यायाम की उपयोगिता के बारे में जागरूक करना है। इस अवसर पर नागपुर (महाराष्ट्र) के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. आकाश सावजी ने बताया कि आज की भागदौड़–भरी जिंदगी, गलत खानपान और नियमित व्यायाम की कमी के चलते घुटनों और जोड़ों का दर्द आम समस्या बन चुका है। ऐसे में नियमित फिजियोथेरेपी के साथ–साथ सही उपचार अपनाकर लोग अपने शरीर का खोया हुआ लचीलापन वापिस प्राप्त कर सकते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उन्होंने कहा कि दवाओं और फिजियोथेरेपी के साथ–साथ अब लोगों में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानि पीआरपी तकनीक भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

पीआरपी तकनीक – इस तकनीक में पीड़ित व्यक्ति के खून से विशेष प्लाज्मा तैयार कर उसे प्रभावित घुटने या जोड़ में इंजेक्ट किया जाता है। यह प्लाज्मा ऊतक की प्राकृतिक मरम्मत को बढ़ावा देता है और दर्द में उल्लेखनीय राहत मिलती है। इस प्रकार स्वयं के रक्त से तैयार यह प्लाज्मा सुरक्षित भी होता है। पीआरपी खासकर उन मरीजों के लिए लाभदायक है, जिन्हें लगातार घुटनों में दर्द रहता हो, पूर्व में कोई लिगामेंट इंजरी हुई हो या खेलकूद से जुड़ी चोटों का सामना करना पड़ता हो। सबसे बड़ी बात यह कि इस तकनीक को बिना सर्जरी के सुरक्षित तरीके से पूरा किया जाता है और परिणाम भी जल्दी मिलते हैं। डॉ. सावजी ने बताया कि पहले लोग सर्जरी को ही अंतिम विकल्प मानते थे, लेकिन पीआरपी जैसी आधुनिक पद्धतियाँ अधिकांश मामलों में सर्जरी की आवश्यकता को टाल देती हैं। इससे मरीज जल्द ही सामान्य जीवन में लौट सकते हैं और उनकी सक्रियता भी बनी रहती है।

पीआरपी क्लाउड विधि – जर्मन पेटेंट तकनीक: डॉ. सावजी के पास पीआरपी की विशेष क्लाउड विधि का अत्यंत प्रतिष्ठित जर्मन पेटेंट उपलब्ध है।

विद्युत बिल शिकायतों के निराकरण हेतु ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कार्यपालन अभियंता (संचा–संधा), म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान और बकाया राशि की वसूली के उद्देश्य से प्रत्येक वितरण केन्द्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

इसके लिए सभी वितरण केन्द्रों के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता एवं प्रभारी अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने–अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर उपभोक्ताओं की विद्युत बिल संबंधी शिकायतों की सुनवाई करें। प्रत्येक शिविर में प्राप्त शिकायतों का विवरण शिविर पंजी में दर्ज किया जाएगा। साथ ही अकुशल/फेल ट्रांसफार्मरों से संबंधित उपभोक्ताओं से बकाया राशि जमा कराते हुए अपात्र ट्रांसफार्मरों को बदलने हेतु पात्र बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक वितरण केन्द्र में पाँच ग्राम पंचायतों का चयन शिविर आयोजन हेतु किया जाएगा। प्राथमिकता उन ग्राम पंचायतों को दी जाएगी, जहाँ पूर्व से ही वितरण ट्रांसफार्मर फेल हो चुके हैं। शिविर से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव से संपर्क कर आयोजन की सूचना दी जाएगी और ग्राम के बकायादार उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

गौ संरक्षण को समर्पित चिंतन बैठक का हुआ आयोजन, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की उठी मांग

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। बृजवासी गौरक्षक सेवा संगठन के तत्वावधान में आर्योदय पब्लिक स्कूल अतरैला में एक दिवसीय चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य गौ संरक्षण और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने हेतु सामाजिक जागरूकता फैलाना था। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रवक्ता सज्जन तिवारी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत कृष्ण कन्हैया एवं गौ माता की प्रतिमा के समक्ष वैदिक पूजन से हुई। मुख्य अतिथि के रूप में ब्रजवासी गौरक्षा सेवा संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष रोशनी मैत्रेय और

विशिष्ट अतिथि प्रदेश मंत्री वैभव केसरवानी उपस्थित रहे। बैठक में चरनोई एवं गोचर भूमि पर चर्चा की गई, जिसमें वैभव केसरवानी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन के लिए आरक्षित भूमि की दशा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में चरनोई भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पूर्णिमा तिवारी, योग शिक्षक संतोष तिवारी और अन्य सदस्यों ने बैठक में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, गौहत्या पर सख्त प्रतिबंध, और गौ आधारित जैविक खेती का प्रोत्साहन जैसी मांगों पर चर्चा की। सज्जन तिवारी ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता, गौ सेवक, युवाजन एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। संगठन ने ग्राम स्तर पर जन जागरण अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनमत तैयार करने की योजना बनाई है।

समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी राखी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जनपद पंचायत मझौली अंतर्गत ग्राम लेडुआ की निवासी राखी चौधरी ने आत्मनिर्भरता की ऐसी मिसाल पेश की है, जो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। राखी पहले छोटे स्तर पर ब्यूटी पार्लर का काम करती थीं। उस समय उनकी वार्षिक आय मात्र 50 से 60 हजार रुपए थी। इतनी सीमित आमदनी में परिवार का खर्च चलाना कठिन हो रहा था और अक्सर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस- निराशा से आशा की ओर

पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय चुरहट में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त राजेश लखानी, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल संभाग के उपायुक्त आर.के. वर्मा, सहायक आयुक्त लेखराज मीणा तथा सहायक आयुक्त एवं संकुल प्रभारी दीक्षा ज्योति मिश्रा के निर्देशन और प्रभारी प्राचार्य डॉ. डी.के. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय, चुरहट (सीधी) में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कार्यक्रम अत्यंत संवेदनशीलता और जागरूकता के साथ आयोजित किया गया।

यह दिवस प्रतिवर्ष 10 सितंबर को वैश्विक स्तर पर आत्महत्याओं की रोकथाम, करुणा को बढ़ावा देने और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, 15–29 वर्ष की आयु वर्ग में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण आत्महत्या है, जो त्वरित और व्यापक हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाता है।

कारण और चुनौतियाँ: कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि अक्सर हम जिन्हें हंसता–खेलता देखते हैं, उनके मन के भीतर पीड़ा का अथाह सागर छिपा होता है। आज के समय में न केवल युवा बल्कि अबोध बच्चे भी आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। कक्षा में होने वाली बुलिंग और साइबर बुलिंग, समाज का बढ़ता दबाव, माता–पिता द्वारा अत्यधिक अपेक्षाएँ और तुलना की प्रवृत्ति, आर्थिक संकट, कर्ज का बोझ, भावनात्मक आघात, व्यंग्य और सामाजिक उपेक्षा जैसे कई कारण बच्चों और युवाओं को निराशा की ओर धकेल रहे हैं।

संकल्प सिंह (टीजीटी अंग्रेज़ी) ने विषय पर अपने विचार रखते हुए सकारात्मक सोच अपनाने पर बल दिया। रिचा (पीजीटी इतिहास) ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आदत डालनी चाहिए। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे अपने परिवार, मित्र या विश्वसनीय व्यक्ति से साझा करना चाहिए। उन्होंने छात्रों को सरकार और एनजीओ द्वारा संचालित विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिनमें टेली–मानस, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और मनोदर्पण जैसी पहलें शामिल हैं।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और छात्र सहभागिता: कक्षा 10वीं की छात्राओं की नाटक मंडली ने इस विषय पर प्रस्तुत लघु नाटिका से सभी की आँखें नम कर दीं। इसमें रिया साहू, वैष्णवी गुप्ता, प्रतिज्ञा पटेल सहित आठ छात्राओं ने भाग लिया। वहीं आसिन भगत और रितिक सिंह ने मर्मस्पर्शी भाषण देकर संदेश दिया कि समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करना ही समाधान है। कक्षा 9 की छात्राओं संध्या शाह और गायत्री देसाई ने चित्रों के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम का संदेश दिया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में वरिष्ठ शिक्षक एस.के. तिवारी (पीजीटी रसायन विज्ञान), रुपेश चौधरी (अर्थशास्त्र), रवि पांडे, ज्योति कुशवाहा एवं पूरे विद्यालय स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। इस आयोजन ने विद्यार्थियों को यह सीख दी कि जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है, निराशा से आशा की ओर बढ़ना ही जीवन का वास्तविक संदेश है।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 3269/स्टोर/2025 रीवा, दिनांक – 11/9/25

निविदा आमंत्रण सूचना वर्ष 2025–26

प्राचार्य शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा द्वारा कंप्यूटर / प्रिंटर कार्टेज / फोटोकॉपी मशीन रिपेयरिंग सम्बन्धित सामग्री के आपूर्ति एवं रख–रखाव का कार्य। इन्वर्टर बैटरी / ए.सी. रिपेयरिंग / सम्बंधित सामग्री के आपूर्ति एवं रख–रखाव का कार्य सी.सी.टी.वी कैमरा रिपेयरिंग एवं सम्बन्धित सामग्री के आपूर्ति एवं रख–रखाव का कार्य। स्टेशनरी सामग्री आपूर्ति हेतु। स्वच्छता सामग्री के आपूर्ति हेतु। विद्युत सामग्री एवं रिपेयरिंग संबंधी कार्य। एल्युमीनियम सेक्शन, दरवाजा, खिड़की, लोहे की जाली सामग्री के आपूर्ति एवं रख–रखाव का कार्य। प्लम्बरिंग मटेरियल रिपेयरिंग एवं सम्बंधित सामग्री के सम्बन्धित सामग्री के आपूर्ति एवं रख–रखाव का कार्य। वाटर कूलर वाटर आर.ओ. प्लांट एवं आर.ओ 10 ली. 25 ली. 50 ली. क्षमता वाले से सम्बंधित सामग्री के क्रय एवं रिपेयरिंग का कार्य। महाविद्यालय की पुरानी/रद्दी उत्तर पुस्तिका एवं न्यूज पेपर के विक्रय हेतु। खेल–कूद से सम्बंधित सामग्री। पुस्तकालय (पुस्तक क्रय) से सम्बंधित सामग्री (द्वितीय अवसर)। महाविद्यालय में टेंट सम्बंधित कार्य (द्वितीय अवत्सर)। फ्लैक्स / बैनर / विनायल / पोस्टर / प्रपत्र एवं मीडिया / प्रचार संबंधी कार्य एवं नोटिस बोर्ड / दीवारों पर पेंट द्वारा लिखावट का कार्य, अलग–अलग आकर में (द्वितीय अवसर)। संगीत विभाग से सम्बंधित वाद्य यंत्र क्रय एवं सुधार का कार्य (द्वितीय अवसर)। अग्निशामक यंत्र रिफिल व नये अग्निशामक यंत्र का कार्य (द्वितीय अवसर)। महाविद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी का कार्य (द्वितीय अवसर)। टैक्सी / इनोवा / इनोवा समकक्ष गाडी एवं बस किराये से लेने के कार्यों (द्वितीय अवसर) हेतु निविदा दिनांक 03.10.2025 शाम 04.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार निविदा की विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी स्टोर शाखा एवं महाविद्यालय की वेबसाइट www.trscollege.com से प्राप्त कर सकते है।

प्राचार्य
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

घुसपैठियों को कौन खदेड़ेगा

2016 में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद को बताया था कि भारत में लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। यह ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है। 2004 में तत्कालीन यूपीए सरकार के गृह राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने खुलासा किया था कि देश के 17 राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में कुल 1 करोड़ 20 लाख 53,950 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मौजूद हैं। ये आंकड़े सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों के थे, जबकि म्यांमार, नेपाल और अन्य देशों से भी अवैध तरीके से लोग भारत में घुसते रहे हैं। अब 2025 में ये तमाम आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ चुके होंगे! बुनियादी आंकड़ा 2 करोड़ भी मान लेते हैं, तो उस अनुपात में घुसपैठियों को देश के बाहर खदेड़ा क्यों नहीं जा रहा है? यदि उनके भी मानवाधिकार की चिंता करें, तो 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद, औसतन हर साल, घुसपैठियों को उनके मूल देश भेजने का आंकड़ा बेहद कम है। गति बेहद धीमी है। दरअसल हम न तो यूपीए की मनमोहन सरकार की कार्रवाई से तुलना के पक्षधर हैं और न ही अमरीका, ब्रिटेन और यूरोप के अवैध प्रवासियों को देश के बाहर करने के अभियानों को उदाहरण मानते हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी 'स्वतंत्रता दिवस' पर लालकिले की प्राचीर से 'राष्ट्रीय डेमोग्राफी मिशन' की घोषणा करते हैं और असम, बंगाल, बिहार की जनसभाओं में घुसपैठ के लिए कांग्रेस को ही कोसते हैं, कांग्रेस को 'घुसपैठियों की रक्षक' करार देते हैं, तो यह घुसपैठ का कोई तार्किक समाधान नहीं है। यह विशुद्ध राजनीति है। प्रधानमंत्री 'राष्ट्रवाद बनाम घुसपैठिए' के जरिए हिंदू-मुसलमान की सियासत कर ध्रुवीकरण को तेज करना चाहते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं। बिहार में तो दो माह में ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लिहाजा घुसपैठियों के खिलाफ हुंकारें समझ में आती हैं। बेशक देश के सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी संतुलन कई जगह बिगड़ चुका है। कई जगह मुसलमान बहुमत में आ चुके हैं और हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। असम में 50 लाख से अधिक और बंगाल में 57 लाख से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के कारण ये समीकरण बदल रहे हैं। नतीजतन सांप्रदायिक दंगों के हालात भी बनते रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में जो हिंदू-विरोधी उत्पात मचाए गए, हिंसक प्रहार किए गए, घर उजाड़ दिए गए, उस परिदृश्य पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला पढ़ा जा सकता है। सवाल है कि सरकार ने असम में एनआरसी की जो कवायद की थी, उसके नतीजों का क्या हुआ? वह प्रक्रिया अचानक रोक क्यों दी गई? प्रधानमंत्री मोदी इस जनसांख्यिकी परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील खतरा मानते हैं। हमारे युवाओं के हिस्से के संसाधन और रोजगार छिन रहे हैं। महिलाओं की इज्जत के साथ छल-कपट, खिलवाड़ किए जा रहे हैं। यकीनन यह विकराल राष्ट्रीय समस्या लगती है, लिहाजा यह प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की प्राथमिक चिंता, बुनियादी सरोकार होना चाहिए।

संपादकीय

आदमी सा जीवन

पीए सिद्धार्थ

झुन्नू लाल मुझे पार्क में एक बैंच पर किसी थिंकर की तरह बैठे मिले। मैंने उन्हें दूर से ही 'जय हिंद' कहा तो वह उछलते हुए मेरे पास पहुंच गए और इतनी आत्मीयता से गले पड़े कि उन्हें छुड़ाना मुश्किल हो गया। उनका यह अंदाज देख कर मुझे अपने विश्व गुरु की याद आ गई। मुझे कुछ असहज पाकर वह बोले, 'क्या हुआ, तुम्हें मेरा गले लगना पसंद नहीं आया? लेकिन मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। दरअसल, आज कुत्तों पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं इतना खुश था कि अपने आपको संभाल नहीं पाया। इस खुशी को साझा करते हुए अगर मैं किसी कुत्ते से इस तरह मिलता, तो वह मुझे अवश्य काट लेता।' मैं उन्हें घूरता हुआ बोला, 'इस फैसले में इतना खुश होने वाली क्या बात है?' वह कहने लगे, 'मुझे इस बात की खुशी है कि कूकर प्रेमियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन पेशियों में ही कुत्तों को निपटा दिया। वरना, कई मामले तो सालों से लटके पड़े हैं। उमर खालिद और उसके साथियों के पांच साल से जेल में होने के बावजूद उसकी जमानत पर महीनों सुनवाई नहीं हो पाई। फिर जब हुई भी तो जमानत नहीं मिली। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों पर दिए गए इस फैसले से प्रसन्न होकर श्वान प्रेमियों को अब 26 अगस्त की बजाय हर महीने की 26 तारीख को कुत्ता दिवस मनाना चाहिए।' मैंने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति को मुंह अंधेरे सुबह या देर रात को अकेले पैदल निकलना पड़े तो ये आवारा या सामुदायिक कुत्ते उनके लिए खतरा बन जाते हैं। हर रोज कुत्तों के काटने के इतने किस्से सामने आते हैं। इसके बावजूद कुत्ता प्रेमी इनके लिए ढाल बन गए। लेकिन आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर इस तरह संगठित होकर कोई आवाज नहीं उठाता। झुन्नू जी मेरी यह बात सुनकर गंभीर होते हुए बोले, 'तुम लोगों की यही समस्या है कि किसी भी बात को समझे बिना हमेशा मुर्गियों की तरह ऊपर-ऊपर से ही चोंच मारते हो। पहली बात है कि कुत्ते सभ्यता के आरंभ से ही हमारे साथी रहे हैं। उनके गुणों की वजह से मनुष्य उन्हें पालता आ रहा है। यह पालन घरेलू भी हो सकता है और सामुदायिक भी। जहां तक कुत्तों की पैरवी करने की बात है, कुत्ते भौंक तो सकते हैं, लेकिन कोर्ट जाकर अपनी बात नहीं रख सकते।

फिर जब कोर्ट आम आदमी की बात नहीं सुनता तो कुत्तों की क्या सुनेगा। कुत्ते अगर किसी बात को लेकर परेशान भी हों तो उनकी बात को समझेगा कौन? जहां तक आदमियों की बात रखने का प्रश्न है तो सबसे पहले तो पीड़ित को ही अपनी बात कहने होगी। जब तक आदमी एकल रूप से अपनी बात नहीं रखेगा, उसकी बात सामूहिक रूप से भी उठानी मुश्किल होगी। सुनो! मैं तुम्हें कुत्तों पर बनी कुछ मजेदार कहावतें सुनाता हूंज।' मुझे दुनिया भर की कहावतें सुनाने के बाद वह बोले, 'दुनिया भर में कुत्तों पर बनी इन कहावतों और मुहावरों से अब तुम्हें पता चल गया होगा कि कुत्ते हमारी जिंदगी का वह महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनके बिना हमारी विकास यात्रा का वर्णन पूरा नहीं हो सकता। आदमी में कुत्ते और कुत्तों में आदमी इस तरह रच-बस गए हैं कि दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं।' झुन्नू जी की बातें और कहावतें सुनकर मुझे लगने लगा था कि कुत्ते सचमुच आदमी की विकास की कहानी का वह महत्वपूर्ण भाग हैं, जिनके बिना हमारी यात्रा अधूरी रहती। इन कहावतों को सुनकर मुझे लगा कि आदमी के जीवन में कुत्ते जितने अहम हैं, उतना ही कुत्तों के जीवन में आदमी अहम है। एक-दूसरे के बिना अब शायद हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बस फर्क है तो इतना कि हम अपने लिए 'कुत्ते सा जीवन' कहावत इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कुत्तों के लिए 'आदमी सा जीवन' अभी खुले तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। जबकि सच यह है कि अधिकांश आदमी 'कुत्तों सा जीवन' जी रहे हैं और कई भाग्यशाली कुत्ते 'आदमी सा।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिज़ोरम, मणिपुर और असम की यात्रा के दौरान हुई घोषणाएं केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से युगांतरकारी मानी जा सकती हैं। मोदी की घोषणाओं और उद्बोधनों से उनका संकल्प साफ झलकता है कि पूर्वोत्तर को भारत की विकास धारा में सशक्त स्थान दिलाया जाएगा। मोदी की ये यात्राएं पूर्वोत्तर की राजनीति और समाज में एक एक नई करवट, नई सुबह साबित हो सकती हैं। मिज़ोरम में उनका संदेश कि पूर्वोत्तर प्रगति का प्रवेशद्वार है, असम में उनका कथन कि पूर्वोत्तर भारत की आत्मा है, और मणिपुर में उनका आत्मीयता- हार्दिक स्पंदन का मरहम ये तीनों मिलकर एक नई दृष्टि, नई दिशा एवं नये संकल्प प्रस्तुत करते हैं।

पूर्वोत्तर मे मोदी : शांति एवं विकास की नई सुबह की आहट

- ललित गर्ग -

प्रधानमंत्री ने यह संकल्प व्यक्त किया कि पूर्वोत्तर को सड़क, रेल और हवाई सेवाओं से देश के हर हिस्से से जोड़ा जाएगा। 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत पड़ोसी देशों से भी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में हिंसा, अशांति और अलगाव की जगह अब शांति, विकास और विश्वास का नया युग शुरू हो रहा है। उन्होंने इन राज्यों के युवाओं को शिक्षा, स्टार्टअप और खेलकूद के लिए विशेष योजनाओं का लाभ देने का वादा किया। मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर की विविध संस्कृति और परंपराएं भारत की असली शक्ति हैं। इनकी पहचान और गौरव को सुरक्षित रखते हुए विकास होगा। इन तीनों राज्यों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह केवल चुनावी वादे नहीं, बल्कि आने वाले 'नए भारत' का रोडमैप है। उनका यह संदेश भी महत्वपूर्ण रहा कि जब पूर्वोत्तर मजबूत होगा, तभी भारत आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगा और तभी नये भारत, विकसित भारत का सपना आकार लेगा।

हालांकि तीनों ही राज्यों की यात्राएं महत्वपूर्ण थीं, परंतु मणिपुर की यात्रा का महत्व विशेष रहा। पिछले डेढ़ वर्ष से हिंसा और अशांति झेल रहे मणिपुर में प्रधानमंत्री की उपस्थिति केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि एक संवेदनशील हस्तक्षेप एवं आत्मीय मरहम थी। दरअसल,राज्य में स्थायी शांति के मार्ग में जो एक सबसे बड़ी बाधा है, वह है पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय और घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लोगों के बीच लगातार कम होता विश्वास। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि दोनों समुदायों की आकांक्षाओं में संतुलन बनाए। ताकि दोनों समुदायों की चिंता और शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जा सके। ऐसा करते हुए मोदी ने दोनों समुदायों की पीड़ा सुनी, संवाद का सेतु बनाया और यह भरोसा दिलाया कि मणिपुर की त्रासदी केवल एक क्षेत्रीय संकट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चुनौती है। यह यात्रा विश्वास बहाली की शुरुआत साबित हुई। लंबे समय से लोगों को शिकायत रही कि उनकी बात दिल्ली तक नहीं पहुँचती। प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने इस दूरी को कम किया और संकेत दिया कि शांति और विकास दोनों को साथ लेकर ही मणिपुर का भविष्य गढ़ा जाएगा। मणिपुर में उनका संकल्प था कि यहां की मातृशक्ति और युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग देगी। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि मणिपुर और पूर्वोत्तर में शांति की राह आसान नहीं है। विस्थापितों का पुनर्वास, न्याय की प्रक्रिया और आपसी विश्वास का पुनर्निर्माण अभी अधूरा है। यदि इन चुनौतियों को ठोस नीतियों और निरंतर संवाद से नहीं सुलझाया गया, तो यह यात्रा केवल प्रतीकात्मक बनकर रह जाएगी।

राजनीतिक दलों और सामुदायिक नेतृत्व की भूमिका भी यहाँ अहम है। यदि वे केवल वोट-बैंक की राजनीति तक सीमित रहेंगे तो शांति की प्रक्रिया बाधित होगी। इसके लिए सामूहिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता आवश्यक है। यह एक ऐसा विवादास्पद मुद्दा था, जिसने कुकी-जो समुदाय के लोगों में असुरक्षा व अशांति पैदा कर दी। जिसे दूर किए जाने की सख्त जरूरत है। दरअसल, कुकी एवं मैतेई समुदायों के हिंसक संघर्ष ने राज्य में मतभेदों को मनभेद में बदल दिया है। कुकी-जो विधायकों के एक समूह, जिसमें भाजपा के भी सात विधायक शामिल हैं, ने कहा है कि 'दोनों पक्ष केवल अच्छे पड़ोसियों के रूप में शांति से रह सकते हैं,लेकिन फिर कभी एक छत के नीचे नहीं।' उनकी मांग रही है कि गैर-मैतेई समुदायों के लिये अलग विधायिका सहित अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाए। यह सोच दोनों समुदायों के बीच गहरे मतभेद को उजागर करती है, जिसने मणिपुर को गहरी क्षति पहुंचायी है। इन स्थितियों में मोदी ने जोर देकर कहा कि पूर्वोत्तर में अब हिंसा, अलगाव और अशांति का युग समाप्त होना चाहिए। मणिपुर में उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया कि शांति ही विकास का आधार है और जब तक सौहार्द स्थापित नहीं होगा, भारत की प्रगति अधूरी रहेगी। यह संदेश न केवल मणिपुर, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए विश्वास बहाली का माध्यम बना। पूर्वोत्तर केवल सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मणिपुर और अन्य राज्यों की स्थिरता का सीधा संबंध पड़ोसी देशों से भारत के रिश्तों और राष्ट्रीय सुरक्षा से है। इसलिए यहाँ की शांति केवल स्थानीय आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अनिवार्यता है।

मणिपुर पिछले डेढ़ वर्ष से एक त्रासद संघर्ष का साक्षी रहा है। हिंसा, आगजनी, पलायन और खून-खराबे ने राज्य की आत्मा को झकझोर दिया। समाज का संतुलन टूट गया, आपसी विश्वास खंडित हो गया और सामुदायिक संबंधों में ऐसी दरारें पड़ गईं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लंबे समय तक राज्य अशांत और असुरक्षित बना रहा। हिंसा के कारणों को समझना ज़रूरी है। सरकार ने समय-समय पर स्थिति को संभालने की कोशिश की, सुरक्षा बल तैनात किए, कर्फ्यू लगाए और संवाद की पहल भी की, परंतु गहरी दरारें मिटाने में ये प्रयास अपर्याप्त साबित हुए। असली चुनौती थी-मनभेदों को मिटाना। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का महत्व यहीं बढ़ जाता है। उन्होंने राज्य में पहुँचकर दोनों समुदायों की पीड़ा को प्रत्यक्ष रूप से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को उच्चतम स्तर पर समझा जा रहा है। उनका यह संदेश कि ÷शांति ही विकास का आधार है और भारत की प्रगति का सपना तब तक अधूरा है जब तक मणिपुर जैसे राज्यों में सौहार्द नहीं लौटता÷-जनमानस में गहराई से उतरा है। मोदी की इस यात्रा ने सबसे पहले विश्वास बहाली की प्रक्रिया को गति दी।

उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि मणिपुर की त्रासदी केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चुनौती है। दूसरा बड़ा प्रभाव यह रहा कि विकास का एक ठोस रोडमैप सामने आया। मोदी ने राज्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में नई परियोजनाओं की घोषणा की। इस प्रकार उन्होंने शांति और विकास को एक-दूसरे के पूरक के रूप में प्रस्तुत किया। यह दृष्टिकोण मणिपुर को केवल शांति की ओर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और प्रगति की ओर भी ले जाने की क्षमता रखता है। तीसरा और शायद सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह है कि इस यात्रा ने पूरे उत्तर-पूर्व के लिए एक सशक्त संदेश दिया। लंबे समय तक उत्तर-पूर्व को 'दूरस्थ' और 'सीमांत' मानकर उसकी समस्याओं को राष्ट्रीय विमर्श में हाशिये पर रखा गया। मोदी ने अपने संदेश से यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तर-पूर्व भारत की विकास यात्रा का अभिन्न अंग है। मणिपुर में उनका जाना और वहाँ की संवेदनशीलता को समझना केवल राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे उत्तर-पूर्व को यह विश्वास दिलाया कि उसकी पीड़ा और आकांक्षाएँ अब भारत की मुख्यधारा की चिंता हैं।

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में शांति की प्रक्रिया अभी अपूर्ण है। कई घाव ताजे हैं। हिंसा में घरबार खो चुके लोग अब भी अपने गाँवों और बस्तियों को लौटने की प्रतीक्षा में हैं। विस्थापितों के पुनर्वास का प्रश्न जटिल है। न्याय और जवाबदेही की प्रक्रिया अभी आरंभिक स्तर पर है। आपसी अविश्वास की परतें पूरी तरह पिघली नहीं हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को केवल एक प्रतीकात्मक घटना मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा। इसे निरंतर प्रयासों और ठोस नीतिगत कदमों से आगे बढ़ाना ज़रूरी है। इस पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनाव होने में अभी डेढ़ साल बाकी है। राज्य में हिंसा की पुनरावृत्ति रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है ताकि विधानसभा चुनाव में देरी न हो। केंद्र सरकार को विधानसभा को लंबे समय तक निलंबित रखने के फायदे और नुकसान का भी आकलन करना होगा। प्रेषकः

विश्व की पहली एआई महिला मंत्री की संवैधानिकता पर सवाल

डिएला एक एआई-पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विकसित किया गया था। यह ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर पहले से ही एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रही थी। इसे पारंपरिक अल्बानियाई वेशभूषा में एक महिला के रूप में चित्रित किया गया है। इसे आर्टिफ़िशियल मंत्री बनाने से अल्बानिया में संवैधानिक सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अल्बानिया के संविधान के अनुसार, मंत्रियों को 18 वर्ष से अधिक आयु का मानसिक रूप से सक्षम नागरिक होना चाहिए।

हरीश शिवनानी

इस सप्ताह राजस्थान के जैसलमेर जिले से भी छोटे देश अल्बानिया ने संसदीय इतिहास में एक ऐसा कदम उठाया है जो दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है। यूरोप महाद्वीप के इस देश के प्रधानमंत्री एडी रामा ने अपने मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक आर्टिफ़िशियल महिला मंत्री डिएला नियुक्त की है, जो मानव न होकर कृत्रिम बुद्धि जनित यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित है। डिएला का अर्थ अल्बानियाई भाषा में सूर्य होता है। अल्बानिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंसिंग विभाग के प्रमुख एनियो कासो ने 12 सितंबर को अल्बानिया की राजधानी तिराना में एआई बॉट मंत्री डिएला का परिचय दिया। यह विश्व की एक ऐसी कैबिनेट मंत्री है जो शारीरिक नहीं हैं। डिएला को सार्वजनिक खरीद विभाग का मंत्री बनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी निविदाओं के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को पारदर्शी, तेज और पूरी तरह जवाबदेह बना कर भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करना है।

डिएला एक एआई-पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विकसित किया गया था। यह ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर पहले से ही एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रही थी। इसे पारंपरिक अल्बानियाई वेशभूषा में एक महिला के रूप में चित्रित किया गया है। इसे आर्टिफ़िशियल मंत्री बनाने से अल्बानिया में संवैधानिक सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अल्बानिया के संविधान के अनुसार, मंत्रियों को 18 वर्ष से अधिक आयु का मानसिक रूप से सक्षम नागरिक होना चाहिए। इस वर्ष हुए संसदीय चुनाव में रामा की सोशलिस्ट पार्टी ने 140 विधानसभा सीटों में से 83 सीटें जीतकर लगातार चौथी बार सत्ता हासिल की जबकि पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति साली बेरिशा के नेतृत्व वाले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के गठबंधन ने 50 सीटें जीतीं। बहुमत के लिहाज से सोशलिस्ट ??पार्टी शासन कर सकती है और ज्यादातर कानून पारित कर सकती है, लेकिन अल्बानिया के संविधान में बदलाव के लिए उसे दो-तिहाई बहुमत यानी 93 सीटों की जरूरत है।

अल्बानियाई राष्ट्रपति बजराम बेगज ने 13 सितंबर को रामा को नई सरकार के गठन का अधिकार सौंपा दिया। विश्लेषकों का कहना है कि इससे प्रधानमंत्री को एआई डिएला के निर्माण और संचालन का अधिकार तो मिल गया है लेकिन सवाल संविधान सम्मत होने का है कि मानव की जगह कृत्रिम आभासी इकाई को मंत्री कैसे बनाया जा सकता है? स्वयं अल्बानियाई राष्ट्रपति के पास भी इसका स्पष्ट ज़वाब नहीं है। पत्रकारों के पूछे जाने पर कि क्या यह संविधान का उल्लंघन है, बेगज डिएला वाला सवाल टाल गए। अल्बानिया के प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे हास्यास्पद और असंवैधानिक करार दिया है। डेमोक्रेट्स के संसदीय दल के नेता गजमेंद बर्धी ने कहा, ÷प्रधानमंत्री की मसखरी को अल्बानियाई राज्य के कानूनी कृत्यों में नहीं बदला जा सकता।÷ अल्बानियाई कानूनी विशेषज्ञों ने भी संवैधानिक चुनौतियों की ओर इशारा किया है। दरअसल अल्बानिया लंबे समय से अपनी सुरक्षा और अन्य हितों के लिए यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन बेहद भर्ष्टाचार के मुद्दे के कारण उसे यह सदस्यता नहीं मिल पा रही है।

भर्ष्टाचार से मुक्ति के लिए उसने यह दांव खेला है। हालांकि विशेषज्ञों की राय में इसके सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन में पश्चिमी बाल्कन, भ्रष्टाचार और कानून के शासन के जानकार डॉ. एंडी होक्साज का मानना है कि अगर एआई को सही ढंग से पेश किया जाए, तो यह मददगार हो सकता है और भ्रष्टाचार-नियंत्रण के लक्ष्य में डिएला मदद कर सकती है। वित्तीय सेवा कंपनी बाल्कन्स कैपिटल की संस्थापक अनीदा बजराकतारी बिचजा का मानना है कि अगर यह एआई मंत्री वास्तविक प्रणालियों में विकसित होती है जो सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और विश्वास में सुधार करती है तो यह रचनात्मक भी हो सकता है। दूसरी ओर यह तथ्य है कि भ्रष्टाचार जैसी जटिल समस्याओं के समाधान के लिए नवीन तकनीकी समाधानों की तलाश एक अहम पहल है लेकिन यह कई गंभीर जोखिमों और चुनौतियों से भरा हुआ कदम है। सबसे बड़ा है जवाबदेही और दायित्त्व का संकट। अगर एआई कोई गलत निर्णय लेती है, जिससे वित्तीय नुकसान होता है या किसी की जान को खतरा होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या डेवलपर? क्या उस मंत्रालय का सचिव? क्या प्रधानमंत्री या फिर खुद एआई अल्गोरिदम? मंत्री एक जवाबदेह व्यक्ति होता है जिसे संसद के सामने जवाब देना होता है और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।

एक एआई सिस्टम को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। एआई मॉडल कैसे निर्णय लेते हैं, यह आम नागरिक के लिए समझना मुश्किल होता है। अगर एआई मंत्री का फैसला नागरिकों के खिलाफ जाता है, तो उस फैसले के पीछे का तर्क समझाना और उसकी समीक्षा करना असंभव हो सकता है। एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह का भी अपना जोखिम है। एआई अपने प्रशिक्षण डेटा से सीखती है। अगर ऐतिहासिक डेटा में मानवीय पूर्वाग्रह (जैसे जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव) शामिल है, तो एआई उन्हीं पूर्वाग्रहों को और मजबूत करके निर्णय लेगी। इससे व्यवस्थागत भेदभाव बढ़ सकता है। इनके अलावा एक गंभीर प्रश्न है सुरक्षा और हैकिंग का। एक एआई सिस्टम साइबर हमलों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। हैकर्स एआई के निर्णयों को तकनीकी चालाकी से अपने हित में बदल सकते हैं।

उदाहरण के लिए, सार्वजनिक खरीद के मामले में, हैकर्स निविदा के परिणामों को अपने पक्ष में करने के लिए एआई में छेड़छाड़ कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार का एक नया और अदृश्य रूप पैदा हो सकता है, जिसे पकड़ना और भी मुश्किल होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मंत्री जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का हिस्सा होता है और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति जवाबदेह होता है। सबसे बड़ी है कानूनी और संवैधानिक चुनौतियां। अधिकांश देशों के संविधान और कानून मंत्री पद के लिए 'मनुष्य' होने की शर्त है। एआई को मंत्री बनाना संवैधानिक संकट पैदा कर सकता है। यह एक अत्यंत जटिल कानूनी सवाल है, जिस पर अभी वैश्विक सहमति नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक एक उपकरण है, शासक नहीं। निर्णय लेने की अंतिम जिम्मेदारी हमेशा मनुष्य के पास ही होनी चाहिए।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

दो सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 18.60 करोड़ रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा दो सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 18 करोड़ 60 लाख 48 हजार स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत कार्यों में रायगढ़ जिले के विकासखंड सारंगढ़ के परसदा ताड़ीपार नहर मरम्मत कार्य हेतु 4 करोड़ 39 लाख 41 हजार रूपए स्वीकृत किए है। स्वीकृत इस योजना के कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्र में रूपांकित सिंचाई क्षेत्र 2501.64 हेक्टेयर में 1012.80 हेक्टेयर की हो रही कम की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार से जशपुर जिले के विकासखण्ड बगीजा की डोड़की व्यपवर्तन योजना का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए 14 करोड़ 21 लाख 7 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। सिंचाई योजना के कार्य पूरा होने पर रूपांकित सिंचाई 688 हेक्टेयर के विरूद्ध 366 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध होगी। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से सिंचाई योजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराने मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला पक्का मकान, लौटी परिवार की मुस्कान

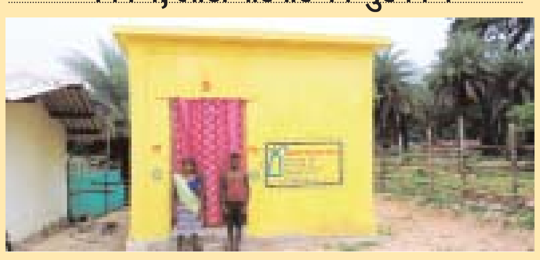

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने विकासखंड गीदम अंतर्गत ग्राम पंचायत कौरगांव के इंदर राम का वर्षों पुराना सपना साकार कर दिया। अब उनके परिवार को सुरक्षित पक्के घर का सुख प्राप्त हुआ है।

कच्चे घर से जूझते थे कठिनाइयों से: इंदर राम एक कृषि मजदूर हैं। लंबे समय से उनका परिवार मिट्टी की दीवार और घास- फूस की छत वाले कच्चे घर में रह रहा था। बरसात के दिनों में टपकती छत और कमजोर दीवारों के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में सांप-बिच्छु छोटे जीव जंतुओं का भय बना रहता था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पक्का मकान बनाना उनके लिए असंभव प्रतीत होता था।

योजना से मिली नई उम्मीद: वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची में नाम आने के बाद इंदर राम को आवास निर्माण हेतु 1 लाख 20 हजार की राशि स्वीकृत हुई। इसके साथ ही मनरेगा के तहत 90 दिवस की मजदूरी का भुगतान भी सीधे उनके बैंक खाते में किया गया।

आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का नया आधार: नया पक्का मकान बनने के बाद इंदर राम के परिवार की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। अब वे सुरक्षित छत तले रह रहे हैं और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी पा रहे हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के प्रति विशेष आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और नई उम्मीदों का प्रतीक है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने किया भारत रत्न विश्वेश्वरैया को नमन

अभियंता दिवस के अवसर पर भारत रत्न विश्वेश्वरैया की जीवनी का किया उल्लेख

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। भारत रत्न डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर अभियंता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने आज नारायणपुर के घड़ी चौक में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। उन्होंने कहा कि विश्वेश्वरैया ने अपने अद्वितीय योगदान और दूरदर्शी सोच से देश के निर्माण और विकास को नई दिशा दी तथा अभियंताओं की भूमिका और उनके योगदान को याद किया।

मंत्री कश्यप ने कहा कि डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक सिविल इंजीनियर, राजनेता और मैसूर के 19वें दीवान थे, जिन्होंने भारत के योगदान में अतुलनीय योगदान दिया। विश्वेश्वरैया की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां में से एक मांड्या में कृष्ण राजा सागर बांध है। भारत के प्रथम अभियंता विश्वेश्वरैया को वर्ष 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, छोटेडोंगर सरपंच संध्या पवार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रताप सिंह मण्डावी, जनपद पंचायत अध्यक्ष पिंकी उसेण्डी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सदस्य एवं नगर पालिका के पार्षदगण, सर्वआदिवासी समाज के संरक्षक रूपसाय सलाम, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई, एसडीएम अभयजीत मंडावी, कार्यपालन अभियंता अशोक चौधरी, कार्यपालन अभियंता विनय वर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं सभी विभागीय अभियंता उपस्थित थे।

ओजोन परत संरक्षण दिवस पर आयोजित होगा पोस्टर एवं इन्वायरोथान प्रतियोगिता

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से मंगलवार 16 सितम्बर को पोस्टर एवं इन्वायरोथान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से नवीन विश्राम गृह, सिविल लाइंस रायपुर में होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण तथा योजना एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री ओ.पी. चौधरी शामिल होंगे।

प्रतियोगिता में स्कूली और महाविद्यालयीन छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। पोस्टर प्रतियोगिता का विषय ÷जलवायु परिवर्तन के कारण और निदान÷ अथवा ÷ओजोन परत संरक्षण - मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल÷ रहेगा। इसे तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, पहला वर्ग 12 से 17 वर्ष, दूसरा 18 से 22 वर्ष और तीसरा दिव्यांगजनों के लिए। प्रतिभागियों को पोस्टर बनाने हेतु अपना हार्ड बोर्ड साथ लाना होगा। इन्वायरोथान प्रतियोगिता का विषय ÷वेस्ट टू वेल्थ÷ तय किया गया है। इसमें कक्षा 12वीं तक, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।

आयुष्मान योजना गरीब एवं मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए सहायक

इससे उन्हें उपचार के लिए अस्पताल का चुनाव करने मिलता है विकल्पः स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया

- गलत क्लेम करने से भुगतान में होती है देरी, इससे ईमानदारी से काम करने वाले संस्थान भी होते हैं प्रभावितः कटारिया
- आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के स्टेकहोल्डर वर्कशाप का आयोजन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आज सोमवार को न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाईन रायपुर में स्टेकहोल्डर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया की परिकल्पना एवं आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला के मागदर्शन में यह वर्कशॉप आयोजित की गई।

योजनांतर्गत जनवरी 2025 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बैठक में जानकारी दी गई थी कि छत्तीसगढ़ में देश में सबसे अधिक फॉड क्लेम पाए गए हैं, और ऐसे अस्पतालों की संख्या के मामले में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। वर्कशॉप में अस्पतालों को जानकारी दी गई कि ट्रिगर क्लेम को कैसे कम किया जा सकता है। साथ ही उन्हे जानकारी दी गई कि भविष्य में भी क्लेम, ट्रिगर नहीं हों। अमित कटारिया द्वारा यह बताया गया कि आयुष्मान योजना गरीब एवं मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए बहुत सहायक है। इस योजना से उन्हें अपने उपचार के लिए अस्पताल का चुनाव करने का विकल्प मिला है। उन्होने बताया कि गलत क्लेम करने से एक दुविधा की शुरुआत हो जाती है। इससे योजना की छवि धूमिल होती है और जनता व अस्पताल का विश्वास डगमगाता है। इससे वास्तविक मरीज जिसे उपचार मिलना चाहिए, अक्सर वंचित रह जाता है। साथ ही अस्पतालों के सही भुगतान में देरी होती है और ईमानदारी से काम करने वाले संस्थान भी प्रभावित होते हैं। और अंततः इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब और वंचित परिवार को उठाना पड़ता है, जिनके लिए यह योजना जीवनरेखा है। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि योजना में अस्पतालों का सही पंजीयन किया जाये और समय-समय पर उनका निरीक्षण किया जाये। शासकीय अस्पतालों द्वारा भी योजना में क्लेम करने के दौरान पूर्ण दस्तावेज़ अपलोड करें जिससे अनावश्यक क्लेम निरस्त न हों। उन्होने आशा जाहिर की कि हमारा राज्य योजना के सकारात्मक मानकों में पूरे देश में प्रथम स्थान पर आए। इस वर्कशॉप में पूरे दिन में विभिन्न बिन्दुओ जैसे, योजना की सामान्य जानकारी, आयुष्मान कार्ड कैसे बनाया जाता है, वय वंदना योजना में आयुष्मान कार्ड कैसे बनाए जाएं, सही तरीके से क्लेम कैसे किए जाएं, दस्तावेज़ कैसे सही तरीके से बनाए जाएं, लिपिकीय त्रुटि कम से कम हों, योजना में क्या करना चाहिए व क्या नहीं करना चाहिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत आभा आई.डी. का उपयोग एवं कम्प्लांएट सॉफ्टवेयर का उपयोग आदि पर जानकारी दी गई।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव का गुजरात दौरा, आधुनिक तकनीक से सशक्त होगी छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था

छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में जुड़ेगी नई तकनीक- मंत्री गजेंद्र यादव

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेंद्र यादव ने अपने तीन दिवसीय गुजरात प्रवास के दौरान अहमदाबाद स्थित भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान द्वारा शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे नवीनतम शोध, तकनीकी उपयोग और नवाचारों का अवलोकन किया।

मंत्री यादव ने कहा कि गुजरात में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। यहां शिक्षा से जुड़े नवाचारों और अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने सीखने और पढ़ाने की प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बना दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए इसी प्रकार की कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ नई तकनीक से जुड़ने का अवसर मिल सके। मंत्री यादव ने कहा कि तकनीक के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है, बल्कि दूरस्थ और दुर्गम अंचलों में रहने वाले विद्यार्थियों तक भी बेहतर शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई जा सकती है। इस दिशा में गुजरात के मॉडल का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

इस अवसर पर शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक लोक शिक्षण ऋतुराज रघुवंशी, गुजरात राज्य के अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने [illegible] के विभिन्न प्रकल्पों और तकनीकी मॉड्यूल्स का गहन अध्ययन किया और इसे छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करने पर चर्चा की। मंत्री यादव का यह दौरा छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में नए आयाम जोड़ने और छात्रों को तकनीक आधारित शिक्षा की ओर अग्रसर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मनेंद्रगढ़, जशपुर समेत छत्तीसगढ़ में 6 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों के निर्माण को मिली प्रशासकीय स्वीकृति

लगभग 14 करोड़ रूपए की लागत से तैयार होगा प्रत्येक फिजियोथेरेपी महाविद्यालय

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को और मजबूत करने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए 6 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों के निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों के निर्माण से न केवल युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन जिलों में नए फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित होंगे उनमें मनेंद्रगढ़, जशपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर शामिल हैं। इन महाविद्यालयों के निर्माण के लिए सरकार ने कुल 83 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रत्येक महाविद्यालय के लिए लगभग 13 करोड़ 93 लाख 71 हजार रुपए (करीब 14 करोड़) का बजट तय किया गया है। यह निवेश न केवल आधुनिक इमारतों और प्रयोगशालाओं के निर्माण पर खर्च होगा बल्कि छात्रों के लिए आवश्यक उपकरणों और अधोसंरचना पर भी किया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश की युवाशक्ति के लिए नई राह खोलेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता का स्वास्थ्य और हमारे युवाओं का भविष्य, दोनों हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। आज जिन 6 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों की स्वीकृति दी गई है, वे केवल संस्थान नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की नई इमारत की नींव हैं। इन महाविद्यालयों से प्रदेश के युवा डॉक्टर और विशेषज्ञ बनकर न केवल छत्तीसगढ़ की सेवा करेंगे बल्कि पूरे देश में राज्य की पहचान को नई ऊँचाइयों तक ले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य शिक्षा नई ऊँचाइयों को छू रही है। 6 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा के अवसर मिलेंगे और फिजियोथेरेपी जैसी महत्वपूर्ण सेवा अब गांव-गांव तक पहुंच सकेगी। यह निर्णय प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के साथ ही युवाओं के लिए नए रोजगार और अवसरों का द्वार खोलेगा।

रेशम की डोर से बुनी आत्मनिर्भरता दंतेवाड़ा की महिलाओं को मिली नई पहचान

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व एवं उनके मार्गदर्शन में कृषि, उद्यानिकी और मत्स्य पालन की तरह ही रेशम विभाग भी हितग्राहियों की आजीविका सशक्त करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विभाग की योजनाओं से लाभान्वित होकर जिले के स्व-सहायता समूह आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। रेशम विभाग द्वारा हितग्राही समूहों को स्वस्थ रेशम कीट अंडे उपलब्ध कराए जाते हैं। इन अंडों से हैचिंग से लेकर कोसा निर्माण तक की संपूर्ण प्रक्रिया हितग्राही स्वयं करते हैं। तत्पश्चात तैयार कोसों के विक्रय से उन्हें आर्थिक आमदनी प्राप्त होती है।

इसी क्रम में शासकीय रेशम केन्द्र, चितालंका की महिला स्व-सहायता समूह ने मलबरी रेशम कीट पालन का सफल संचालन कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

इस वर्ष इन टसर रेशम कीट पालकों ने तेरह सौ स्वस्थ अंडों से 45 दिनों की अवधि में 45 हजार नग डाबा कोसा का उत्पादन किया गया। इन के विक्रय से समूह को 72 हजार 300 सौ रुपए की आय प्राप्त हुई। यह प्रथम फसल से हुई आमदनी समूह की महिलाओं के उत्साह और आत्मविश्वास को दोगुना कर रही है।

अब समूह की महिलाएँ इस वित्तीय वर्ष में दूसरी एवं तीसरी फसल लेने के लिए पूरी तरह तैयार और प्रेरित हैं। यह पहल दंतेवाड़ा जिले में आजीविका संवर्धन और महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण बनकर उभर रही है।

सुकमा जिले में गुट्टागुड़ा एनीकट कम काजवे निर्माण के लिए 2 करोड़ 52 लाख रुपए की मिली प्रशासकीय स्वीकृति

60 हेटेयर भूमि पर मिलेगी सिंचाई सुविधा

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राज्य शासन ने सुकमा जिले के विकासखण्ड सुकमा अंतर्गत गुट्टागुड़ा एनीकट कम काजवे गीदम नाला पर निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना पर कुल 251.81 लाख (रुपये दो करोड़ इक्यावन लाख इक्यासी हजार) का व्यय स्वीकृत किया गया है। योजना पूरी होने के उपरांत क्षेत्र के कृषकों को खरीफ मौसम में लगभग 60 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, साथ ही जल संवर्धन, निस्तारी और पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी। यह परियोजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है तथा इसके लिए आवश्यक अनुशंसा समिति की बैठक में दिनांक 23 जुलाई 2025 को की गई थी।

निर्माण कार्य को स्वीकृत राशि और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व तकनीकी स्वीकृति (ञ्जस्) एवं ड्रॉइंग-डिज़ाइन का अनुमोदन आवश्यक होगा। निविदा प्रक्रिया केवल 75 प्रतिशत बाधा-रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही प्रारंभ की जाएगी तथा इसे पूर्णतः पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक रखने के निर्देश दिए गए हैं।

परियोजना में व्यय केवल स्वीकृत बजट शीर्ष के अंतर्गत ही किया जाएगा। दर अथवा कार्य की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की स्थिति में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अनिवार्य होगी। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मितव्ययिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उत्तरदायित्व तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य अभियंता को परियोजना पर नियंत्रण रखने एवं वित्तीय अनुशासन का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन का यह प्रयास क्षेत्रीय कृषकों के हित में सिंचाई एवं जल संरक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

कबीरधाम जिले में शुरू हुई सौर ऊर्जा क्रांति की कहानी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना कबीरधाम जिले में सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई राह प्रशस्त कर रही है। कबीरधाम जिले के 11 परिवारों ने अपने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कर यह संदेश दिया है कि यह योजना केवल बिजली बिल की बचत का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक जनआंदोलन है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कबीरधाम जिले में योजना का क्रियान्वयन तीव्र गति से हो रहा है। अब तक जिले में 94 से अधिक हितग्राही वेंडरों का चयन कर चुके हैं तथा कई लाभार्थियों को सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। आने वाले महीनों में हजारों परिवार इस योजना से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

कबीरधाम जिले के 11 परिवारों ने योजना का लाभ उठाते हुए अपने घरों की छतों पर 1 से 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल स्थापित किए हैं। इनमें योगेन्द्र सिंह कश्यप (राजमहल चौक, कवर्धा), नरेश कुमार चंद्रवंशी एवं रितेश कुमार चंद्रवंशी (दौजरी), सतीश कुमार धवलकर (मठपारा वार्ड-3), लीना तिवारी (मठपारा वार्ड-12), रोशन राम (नागर जवादन रोड), कुमारी देवी सोम (श्याम नगर), ओंकार साहू (रामनगर), सरोज बाई ठाकुर और माधुरी (कालिका नगर) शामिल हैं। इन सोलर पैनलों से प्रतिमाह लगभग 300 यूनिट मुफ्त बिजली का उत्पादन हो रहा है। अतिरिक्त बिजली को सीएसपीडीसीएल ग्रिड में भेजकर ये परिवार आगामी बिलों में क्रेडिट का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं।

योगेन्द्र सिंह कश्यप ने बताया कि पहले हर माह बिजली बिल की चिंता रहती थी, अब सोलर पैनल लगने से यह समस्या समाप्त हो गई है। नरेश कुमार चंद्रवंशी, ग्राम दौजरी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से आत्मनिर्भरता का अनुभव हो रहा है। ÷अब हम केवल उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी बन गए हैं।÷ लीना तिवारी ने बताया कि सोलर से घर की जरूरतें पूरी हो रही हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजने से आगामी बिलों में भी लाभ मिल रहा है। सतीश कुमार धवलकर ने कहा कि सूर्यघर योजना से घर रोशन हो गया है और खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने जिले के प्रत्येक परिवार से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।

कबीरधाम जिले के अधीक्षण अभियंता रंजीत घोष ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर सिस्टम लगाने पर 45 हजार रुपए से लेकर 1 लाख 8 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए प्राप्त प्रत्येक आवेदन को शामिल कर लाभान्वित किया जाएगा। यह योजना न केवल बिजली बिलों में बचत और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए एक ऊर्जा क्रांति का आधार भी बन रही है।

कुनबी पटेल समाज के महिला सम्मेलन, तीन जिलों से 1000 महिलाएं पहुंची

कुरीतियां रोकने और बेटियों को निडर बनाने पर चर्चा

खरगोन, एजेंसी। खरगोन के बलगांव आश्रम में कुनबी पटेल समाज का महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें खरगोन, धार और बड़वानी जिलों से करीब एक हजार महिलाएं शामिल हुईं।

सम्मेलन में महिलाओं ने समाज में फैल रही कुरीतियों को रोकने, शिक्षा को बढ़ावा देने और अच्छे संस्कारों पर जोर दिया। युवतियों को सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की सलाह दी गई।

कुरीतियों और नशे दूर रहने की दी सलाह

कार्यक्रम में यह भी तय किया गया कि मृत्युभोज में होने वाली फिजूलखर्ची को रोका जाए, नशे और बुरी आदतों से दूर रहा जाए और विवाह समारोह में गरीब परिवारों की मदद की जाए। बेटियों को निडर और आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया गया।

नीट में सफल हुई छात्राओं का किया सम्मान

इस मौके पर खरगोन जिला इकाई का गठन किया गया। इसमें बालसमुद की पूजा रमेश पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया गया। धामनोद की आशा संतोष पटेल और खरगोन की रेखा हुकुम पटेल उपाध्यक्ष बनीं, जबकि सारिका संतोष पटेल को सचिव का पद दिया गया।

सम्मेलन में नीट परीक्षा में सफल छात्रों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठजन और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

बड़वानी-इंदौर रूट पर बस टाइमिंग विवाद में जमकर हुई मारपीट

बड़वानी, एजेंसी। बड़वानी में मंगलवार सुबह 7 बजे बस टाइमिंग को लेकर विवाद में हिंसा की घटना सामने आई। विश्वास बस के एजेंट और उनके साथियों ने कुमावत बस के मालिक और कंडक्टर पर हमला कर दिया। घटना करंजा चौराहे और रेवा सर्किल पर हुई।

कुमावत बस के मालिक यशवंत का कहना है कि सुबह 5 बजे करंजा चौराहे पर उनकी बस के आगे विश्वास बस खड़ी थी। जब उन्होंने आगे बढ़ने को कहा तो विश्वास बस के एजेंट महेश ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

इसके बाद कुछ लोगों को बुलाकर रेवा सर्किल पर उनकी दूसरी बस के कंडक्टर को भी पीटा। कंडक्टर को गंभीर चोटें आई हैं और वह शहर के निजी अस्पताल में भर्ती है। यशवंत का आरोप है कि आरटीओ द्वारा तय समय सीमा में बसें चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने इस मामले में पहले ही पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले सेंधवा-जुलवानीया के बीच एक बस को आग लगा दी गई थी, जिसमें कई यात्रियों की जान चली गई थी।

यह घटना बस स्टाफ और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। पुलिस अधीक्षक से लेकर प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बड़वानी-इंदौर रूट पर बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

ट्रेन में पकड़ा चोर, यात्रियों ने जमकर धुनाई की

बैग चोरी कर दोस्तों को दिए, बोला- पंडित हूं, यात्री बोले- मार पड़ी तो या अल्लाह कहने लगा

खंडवा, एजेंसी। मुंबई से बनारस जा रही महानगरी एक्सप्रेस में चोरी करते हुए एक चोर को रंगेहाथ पकड़ा गया। उसके दो साथी चोरी का सामान लेकर भाग गए। यात्रियों ने चोर की पिटाई की और खंडवा स्टेशन पर उसे जीआरपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ में चोर ने खुद को पंडित बताया।

यात्रियों के अनुसार, भुसावल के पास चोर बोगी में आया और एक-दो बैग और पर्स चोरी किए। यात्री अंकुश शुक्ला ने बताया कि चोर ने चोरी किए गए सामान अपने दोस्तों को दे दिए थे। पकड़े जाने पर चोर ने कहा कि वह पंडित है, क्योंकि बोगी में मौजूद कुछ लोग पंडित थे। पिटाई के दौरान वह अल्लाह, अल्लाह बोलने लगा।

भीड़ ने चोर को बांधकर पुलिस के सुपुर्द किया : यात्रियों ने चोर को ट्रेन में बांध दिया और खंडवा स्टेशन पर जीआरपी पुलिस को सौंपा। यात्रियों ने कहा कि एसी-3 में बिना टिकट यह चोर यात्री बनकर घुसा और कई यात्रियों के बैग और पर्स चुराए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ इस तरह के लोग दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं और ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए।

पत्नी का पर्स चोरी कर दोस्त को दिया: खंडवा निवासी जफर अंसारी ने बताया कि बदमाश ने उनकी पत्नी का पर्स चोरी किया, जिसमें नकदी, मोबाइल और दवाईयां थीं। चोरी किए गए पर्स को बाद में चोर ने अपने साथी को दे दिया। इसके बाद उन्होंने चोर को पकड़ लिया।

चोर ने सुल्तानपुर का रहने वाला बताया: जीआरपी पुलिस को पूछताछ में चोर ने अपना नाम अभिजीत लक्ष्मीकांत मिश्रा और सुल्तानपुर निवासी बताया। उसने कहा कि वह परिवार के साथ सफर कर रहा था और उसने कोई चोरी नहीं की। पुलिस ने जफर अंसारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर चोर को हिरासत में ले लिया।

टाइमलाइन: मंगलवार सुबह 6.30 बजे भुसावल से पहले चालीसगांव के पास चोर को पकड़ा। उसी दौरान चोर को पकड़कर धुनाई कर दी और उसे बांध दिया।

सुबह 9 बजकर 55 मिनट पर ट्रेन खंडवा स्टेशन पर पहुंची। यहां चोर को जीआरपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

10 बजकर 15 मिनट पर खंडवा निवासी जफर अंसारी ने पुलिस से लिखित शिकायत की। जीआरपी थाने में चोर ने खुद का नाम अभिजीत लक्ष्मीकांत मिश्रा बताया, वहीं खड़े फरियादी जफर अंसारी ने कहा कि, यह तो पीटने पर अल्लाह, अल्लाह बोल रहा था।

पश्चिम बंगाल के युवक का निकाला जुलूस, वीडियो वायरल होने पर हिंदूवादी संगठन में आक्रोश

उज्जैन, एजेंसी। उज्जैन में एक युवक का पुलिस ने जुलूस निकाला है। वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला है और नरवर में रहकर मजदूरी कर रहा था। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह गाय से अप्राकृतिक कृत्य करता दिखाई दे रहा है। घटना 13 सितंबर की बताई जा रही है। नरवर पुलिस ने आरोपी इतकार अली पिता हिदायत को गिरफ्तार कर लिया है। नरवर पुलिस ने बताया कि शनिवार रात करीब 12.45 बजे प्रॉपर्टी ब्रोकर प्रदीप प्रजापति अपने दोस्त अंकित चौधरी के साथ हरनावदा रोड जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति नरवर प्राइड कॉलोनी के सामने गाय से अप्राकृतिक कृत्य करते हुए दिखाई दिया। उन्होंने इसका वीडियो बना लिया था। फिर उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गया। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश जताया है। हिंदूवादी संगठन की नीलू चौहान का कहना है कि मैं इस कृत्य की कड़ी निंदा करती हूं। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

उधना-बलिया के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन रतलाम, नागदा स्टेशन पर रहेगा स्टॉपेज

दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे लगाएगी

रतलाम, एजेंसी। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उधना-बलिया के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन रतलाम मंडल से होकर गुजरेगी और दोनों दिशाओं में 3-3 फेरे लगाएगी।

गाड़ी संख्या 09041 उधना-बलिया स्पेशल 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक हर गुरुवार को उधना से 06:40 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन शुक्रवार को 20:15 बजे बलिया पहुंचेगी।

दाहोद (12:12/12:14), रतलाम (13:35/13:45), नागदा (14:38/14:40), उज्जैन (15:55/16:05) और शुजालपुर (17:58/18:00) पर इसका ठहराव रहेगा।

बलिया से 26 सितंबर से होगी शुरुआत

गाड़ी संख्या 09042 बलिया-उधना स्पेशल 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हर शुक्रवार को 23:30 बजे बलिया से चलेगी और रविवार को 12¬45 बजे उधना पहुंचेगी।इसका शुजालपुर (01:27/01:29), उज्जैन (03:40/03:50), नागदा (04:40/04:42), रतलाम (05¬20/05¬30) और दाहोद (07:01/07:03) पर रविवार को ठहराव होगा।

इन स्टेशनों पर मिलेगा स्टॉपेज

यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, भरूच, विश्वामित्री, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, शुजालपुर, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, गंज बसौदा, बीना, ललितपुर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ओरई, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चुनार, जीवनाथपुर, वाराणसी, जौनपुर, औंड़िहार और गाजीपुर सिटी में रुकेगी।

14 थर्ड एसी कोच होंगे

यह ट्रेन 14 थर्ड एसी कोच के साथ चलाई जाएगी। रेलवे का मानना है कि इस फैसले से त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

सीएम राइज स्कूल के शिक्षक की डूबने से मौत टाइफाइड से पीड़ित थे, खेत पर घूमने गए थे

तालाब में पानी पीने के दौरान हादसे की आशंका

रायसेन, एजेंसी। गैरतगंज के टेकापार कॉलोनी में रहने वाले सीएम राइज स्कूल के 37 वर्षीय शिक्षक हेमंत उर्फ गोलू ठाकुर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सोमवार को वे अपनी बाइक से जुझारपुर रोड स्थित अपने खेत गए थे।

देर तक घर न लौटने और मोबाइल बंद होने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। दोपहर 12 बजे खेत में बने कच्चे तालाब के किनारे उनकी बाइक मिली। तालाब में एक चप्पल तैरती दिखी। पुलिस ने मौके पर

पहुंचकर तालाब से शव बरामद किया। हेमंत पिछले कुछ दिनों से टाइफाइड से पीड़ित थे। माना जा रहा है कि प्यास लगने पर वे पानी पीने तालाब की ओर गए और फिसलकर 25-30 फीट गहरे पानी में डूब गए। उनके परिवार में पत्नी, पुत्र और माता-पिता हैं। थाना प्रभारी डीपी लोहिया के अनुसार मामला संदिग्ध नहीं है। स्थानीय लोगों और परिजनों के बयान से पता चला है कि मृतक का परिवार सीधा-सादा था और किसी से कोई विवाद नहीं था। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सोमवार शाम को अंतिम संस्कार किया गया। मिलनसार स्वभाव के कारण पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

सीहोर में एक महीने में 2 बार आया बिजली बिल

नाराज उपभोक्ताओं ने किया बिजली विभाग के ऑफिस में किया हंगामा

सीहोर, एजेंसी। सीहोर में बिजली कंपनी के स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिलों को लेकर लोगों में आक्रोश है। उपभोक्ताओं का कहना है कि एक महीने में दो से तीन बार बिल आ रहे हैं। खपत से ज्यादा राशि के बिल आने से हजारों रुपए का बोझ पड़ रहा है और परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है।

इसी मुद्दे पर एक महिला उपभोक्ता का गुस्सा फूट पड़ा। वह बिजली कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से जमकर बहस की। आए दिन ऐसे विवाद बिजली दफ्तर में देखने को मिल रहे हैं। बढ़े हुए बिलों और गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर उपभोक्ता पहले ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं।

कांग्रेस ने बिजली कंपनी का पुतला फूंका

जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी विरोध जताते हुए कोतवाली चौराहे पर बिजली कंपनी का पुतला दहन किया था। उपभोक्ता घनश्याम यादव का कहना है कि एक महीने में दो-दो बिल आना गलत है, लेकिन अधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं कर रहे। इस मामले में बिजली कंपनी के एई अतुलेश सिंह का कहना है कि उपभोक्ताओं को अलग-अलग महीनों के बिल ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रम क्यों बन रहा है, इसका कारण स्पष्ट नहीं है।

बेटी बोली- मां ने खाना नहीं बनाया, इसलिए मार डालालेडी हेड कॉन्स्टेबल की पीट-पीटकर हत्या

सीधी, एजेंसी। सीधी में लेडी हेड कॉन्स्टेबल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पति ने विवाद के बाद बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

घटना सोमवार रात करीब 11 बजे की है। पुलिस ने बताया कि हेड कॉन्स्टेबल सबिता साकेत (38) और उनके पति वीरेंद्र साकेत (40) का लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार रात भी दोनों का झगड़ा हुआ। इसी दौरान वीरेंद्र ने सबिता पर हमला कर दिया। गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सबिता कमर्जी थाने में पदस्थ थीं और पति के साथ पुलिस लाइन में रहती थीं।

बेटी से बात कर रही थी, तभी हुआ झगड़ा: सबिता

और वीरेंद्र की शादी को 26 साल हो गए हैं। दोनों का एक बेटा (24) और बेटी (20) है। बेटी ने बताया, भाई भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। कल रात मैं नानी के घर थी। रात में मां से फोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान खाना नहीं बनाने को लेकर मां और पापा में झगड़ा हुआ। मैं फोन सब सुन रही थी। पापा ने मां की हत्या कर दी। इसके बाद मैंने पुलिस को सूचना दी।

रात 9 बजे ड्यूटी से लौटी थी सबिता: कमर्जी थाना प्रभारी विवेक द्विवेदी ने बताया कि सोमवार रात 9 बजे तक सबिता ने ड्यूटी की और घर चली गई थी। उसके पति की खुद की गाड़ी थी, जिसे उसने जल संसाधन विकास में लगाया है। जहां वह ड्राइवर का काम करता है।

सुबह पुलिस को जानकारी मिली: मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली। कोतवाली थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके को सील कर दिया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

राजकीय सम्मान के साथ विदा किया: इस घटना से परिवार के साथ ही पुलिस महकमे में शोक की लहर है। डीआईजी हेमंत चौहान ने बताया, हमारे पुलिस विभाग के लिए यह अपूर्णिय क्षति है। हमने पीड़ित परिवार को तात्कालिक 1 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करा दी है। हेड कॉन्स्टेबल को राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया है।

डीआईजी ने बताया कि एसपी ने पूरे जिले में नाकाबंदी करवा दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी पहले भी पत्नी से मारपीट किया करता था। इसे लेकर किसी प्रकार की शिकायत मिली थी या नहीं, इसका पता कराएंगे।

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की तो नहीं दिया राशन

छतरपुर में दुकानदार बोला : पहले शिकायत वापस लो, फिर मिलेगा राशन

छतरपुर, एजेंसी। छतरपुर जिले की बिजावर तहसील के पिपट सहकारी समिति की राशन दुकान का मामला सामने आया है। यहां मजदूर अरविंद सेन को शिकायत वापस लेने के दबाव के बाद ही पूरा राशन मिला।

जून महीने में अरविंद को 3 किलो शक्कर मिलनी थी। लेकिन दुकानदार भरत राजपूत ने सिर्फ 1 किलो दी और पोर्टल पर 3 किलो की एंट्री कर दी। इस पर अरविंद ने 181 सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई।

पहले शिकायत वापस लो, फिर राशन लो

सितंबर का राशन लेने जब अरविंद दुकान पहुंचा, तो सेल्समैन ने शर्त रख दी कि पहले शिकायत वापस लो, तभी राशन मिलेगा। इस दौरान का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें सेल्समैन कह रहा है कि उसे अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है।

अरविंद का कहना है कि दुकान पर अन्य लोगों को भी परेशान किया जाता है और समय पर राशन नहीं मिलता। मामला बढ़ा तो बिजावर विधायक राजेश शुक्ला के बेटे धनंजय के हस्तक्षेप के बाद अरविंद को तीन माह का राशन दिया गया और शिकायत बंद कराई गई। इस मामले में भास्कर ने जब सेल्समैन भरत राजपूत से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

नर्मदापुरम की आईएएस जोड़ी का ग्वालियर तबादला इटारसी एसडीएम नगरनिगम अपर आयुक्त

पिपरिया एसडीएम बनीं कार्यकारी संचालक

नर्मदापुरम, एजेंसी। मध्यप्रदेश में सोमवार रात को 18 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। इसमें नर्मदापुरम जिले के इटारसी एसडीएम और पिपरिया एसडीएम का ग्वालियर में स्थानांतरण हुआ।

इटारसी एसडीएम आईएएस टी प्रतीक राव को ग्वालियर नगर निगम में अपर आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। टी प्रतीक राव 2021 बैच के आईएएस अफसर हैं और दो साल से इटारसी एसडीएम के पद पर कार्यरत थे।

उनके कार्यकाल में इटारसी में ऐतिहासिक धरोहर, शहर की सुंदरता और जीवंत संस्कृति को दर्शाती तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सराहा।

अनिशा श्रीवास्तव को एमपी औद्योगिक विकास निगम में नया पद

पिपरिया एसडीएम आईएएस अनिशा श्रीवास्तव को ग्वालियर स्थित मप्र औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यकारी संचालक बनाया गया है। अनिशा श्रीवास्तव भी 2021 बैच की आईएएस अफसर हैं और टी प्रतीक राव की पत्नी हैं।

पिछले साल पिपरिया एसडीएम पद पर रहते हुए उन्होंने पचमढ़ी में हुई कैबिनेट बैठक और रक्षामंत्री, गृहमंत्री के प्रवास पर बेहतर व्यवस्थाओं के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी।

45.50 लाख की डकैती में फरार आरोपी गिरफ्तार-8 महीने से फरार था, पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर पकड़ा

सागर, एजेंसी। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में व्यापारी से 45.50 लाख रुपए की डकैती के मामले में 8 महीने से फरार आरोपी पप्पू पटेल को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है।

21 दिसंबर 2024 को खुरई रोड ओवरब्रिज पर सुबह करीब 6 बजे व्यापारी सुनील लहरवाली निवासी सिंधी कैंप के साथ लूट हुई थी। बदमाशों ने आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उनका बैग छीन लिया था, जिसमें 45.50 लाख रुपए नगद थे।

अब तक 12 आरोपी जेल भेजे जा चुके: वारदात की जांच में पुलिस ने पहले 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी जब्त की थी। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मिलकर डकैती की योजना बनाई थी और रकम छुपाई थी। सभी को कोर्ट पेश कर जेल

भेज दिया गया था।

लोकेशन ट्रेस कर दबिश दी गई: पुलिस और साइबर टीम लगातार फरार आरोपी पप्पू की तलाश कर रही थी। उसकी लोकेशन कनेरा के पास मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पप्पू पिता इमरत पटेल (उम्र 33 वर्ष), निवासी कनेरा देव है।

शेष नकदी की तलाश जारी: मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में जुर्म कबूल किया है। शेष नकदी की बरामदगी के लिए जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी से डकैती की पूरी वारदात को लेकर भी पूछताछ की जा रही है।

एथलेटिक बिलबाओ को झटका, पूरे सीजन बाहर रहेंगे मिडफील्डर बेनात प्राडोस

मैड्रिड, एजेंसी । एथलेटिक बिलबाओ को 11 साल बाद चैंपियंस लीग में वापसी से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। मिडफील्डर बेनात प्राडोस को एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट (एसीएल) की गंभीर चोट लगी है। 24 वर्षीय प्राडोस पिछले हफ्ते ट्रेनिंग के दौरान अपना बायां घुटना चोटिल करवा बैठे थे, जिसके चलते उन्हें पूरे सीजन बाहर बैठना पड़ेगा।

क्लब की ओर से बयान में कहा गया है, एथलेटिक क्लब की मेडिकल टीम की तरफ से किए गए टेस्ट से पता चला है कि फर्स्ट-टीम खिलाड़ी बेनात प्राडोस के बाएं घुटने के एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट (एसीएल) में गंभीर चोट आई है। जल्द ही सर्जरी की तारीख तय की जाएगी। प्राडोस की फिटनेस को लेकर नियमित अपडेट दिए जाएंगे।

कोच अर्नेस्टो वाल्वरडे की रणनीति में प्राडोस को मिकेल जौरेगिजार और चोटिल इनिगो रुइज डी गैलारेटा के बाद सेंट्रल मिडफील्ड में तीसरी पसंद माना जाता था। उनसे चैंपियंस लीग, ला लीगा, कोपा डेल रे और स्पेनिश सुपर कप जैसे टूर्नामेंट्स में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही थी।

एथलेटिक की यूथ एकेडमी से निकले प्राडोस ने पिछले सीजन 45 मैच खेले थे। दूसरे डिवीजन की टीम मिरांडेस के लिए लोन से लौटने के बाद पिछले सीजन में 33 मैच खेले थे।

एथलेटिक क्लब मंगलवार शाम अपने चैंपियंस लीग अभियान की शुरुआत प्रीमियर लीग टीम आर्सेनल के खिलाफ मुकाबले के साथ करेगा। इस मिडफील्डर की कमी को पूरा करने के लिए अर्नेस्टो वाल्वरडे एक और अनुभवी मिकेल वेस्गा और बी-टीम के एलेजांद्रो रेगो की मदद लेंगे।

चैंपियंस लीग के ग्रुप चरण/लीग चरण में एथलेटिक क्लब ने आखिरी बार 2014/15 सीजन में हिस्सा लिया था। इससे पहले टीम 1998/99 में ही खेली थी।

स्पेनिश टीम ने पिछले सीजन यूईएफए यूरोपा लीग के लीग चरण में अपने सभी चार घरेलू मैच जीते थे। इसके अलावा, उन्होंने राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल के घरेलू मुकाबलों में रोमा को 3-1, जबकि रेंजर्स को 2-0 से शिकस्त दी थी, लेकिन सेमीफाइनल के पहले चरण में उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ अपने ही घरेलू मैदान पर 3-0 से हार का सामना करना पड़ा।

चार मौके, जब एक ही टी20 पारी में छूटे 6 कैच

नई दिल्ली, एजेंसी। श्रीलंका और हांगकांग के बीच सोमवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का आठवां मैच खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में हांगकांग की टीम ने छह कैच टपकाए। इसी के साथ यह टीम उन देशों के साथ शामिल हो गई, जिन्होंने टी20 मैच की एक ही पारी में छह कैच छोड़े।

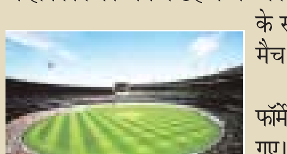

इससे पहले तीन मौकों पर टी20 फॉर्मेट की एक ही पारी में छह कैच टपकाए गए। साल 2009 में भारतीय टीम ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया था। वहीं, साउथ अफ्रीका ने साल 2017 में श्रीलंका के विरुद्ध एक ही टी20 पारी में छह कैच छोड़े थे। यह मुकाबला केपटाउन में खेला गया। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम भी शामिल है, जिसने साल 2024 में स्कॉटलैंड के विरुद्ध ग्रोस आइलेट में खेले गए टी20 मुकाबले में छह कैच छोड़े थे। मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी हांगकांग की टीम ने 4 विकेट खोकर 149 रन बनाए। इस टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। जीशान अली और अंशुमान रथ के बीच 4.5 ओवरों में 41 रन की साझेदारी हुई। जीशान 17 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 23 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे नंबर पर बाबर हयात बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन 4 रन से ज्यादा टीम के खाते में नहीं जोड़ सके। हांगकांग की टीम ने 8.4 ओवरों में 2 विकेट खोकर 57 रन बना लिए थे। यहां से अंशुमान रथ ने निजाकत खान के साथ तीसरे विकेट के लिए 61 रन जुटाए। अंशुमान 46 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हुए, जबकि निजाकत खान ने 38 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 52 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी खेमे से दुष्मंथा चमीरा ने 2 शिकार किए, जबकि वानिंदु हसरंगा और दासुन शनाका ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। इसके जवाब में श्रीलंका ने 18.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। श्रीलंका की ओर से पाथुम निसांका ने 44 गेंदों में सर्वाधिक 68 रन बनाए। उनकी इस पारी में 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे। हांगकांग की ओर से कप्तान यासिम मुर्तजा ने सर्वाधिक 2 शिकार किए, जबकि आयुष शुक्ला, एहसान खान और एजाज खान ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

अपोलो टायर्स टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सर बनी :कंपनी हर मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपए देगी, 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर होगी। कंपनी हर मैच पर लगभग 4.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी ।कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक के लिए हुआ है और इस दौरान 130 मैच खेले जाएंगे।BCCI के एक अधिकारी ने मंगलवार को PTI को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, अपोलो टायर्स के साथ समझौता हो गया है। हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। इससे पहले ड्रीम-11 भारतीय टीम की टाइटल स्पॉन्सर थी। कंपनी हर मैच के लिए BCCI को 4 करोड़ रुपए देती थी। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू होने के बाद BCCI ने ड्रीम 11 से करार खत्म कर दिया था। भारतीय टीम एशिया कप में बिना स्पॉन्सरशिप के खेल रही है, क्योंकि ड्रीम-11 से पहले ही करार खत्म हो चुका है।BCCI ने 2 सितंबर को स्पॉन्सरशिप टेंडर जारी किए BCCI ने 2 सितंबर को स्पॉन्सरशिप के लिए टेंडर जारी किए थे। इसके अनुसार अल्कोहल, तंबाकू, सट्टेबाजी, रियल मनी गेमिंग (फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग को छोड़कर), क्रिप्टोकरेंसी और पोर्नोग्राफी या जो कंपनी सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचने का काम करे।

एशिया कप : निर्णायक मुकाबले में उतरेंगी अफगानिस्तान-बांग्लादेश की टीम

नई दिल्ली, एजेंसी । बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मंगलवार को एशिया कप 2025 का नौवां मैच खेला जाना है। यह मुकाबला अगले दौर में पहुंचने के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है।

ग्रुप-बी की प्वाइंट्स टेबल में श्रीलंकाई टीम शुरुआती दोनों मैच जीतकर शीर्ष पर मौजूद है। वहीं, अफगानिस्तान की टीम हांगकांग के खिलाफ अपना पहला मैच 94 रन से जीतकर दूसरे स्थान पर है।

बांग्लादेश ने हांगकांग के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 7 विकेट से जीता, जिसके बाद श्रीलंका के हाथों उसे 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। यह टीम तीसरे पायदान पर मौजूद है। अपने तीनों मुकाबले गंवाकर हांगकांग की टीम का अभियान समाप्त हो गया है।

इस मुकाबले में बांग्लादेश को कप्तान लिटन दास और तंजीद हसन से बल्लेबाजी में उम्मीद होगी, जबकि गेंदबाजी में तस्कीन अहमद और मेहदी हसन विपक्षी टीम को परेशान कर सकते हैं।

वहीं, अफगानिस्तान के खेमे को सेदिकुल्लाह अटल और इब्राहिम जादरान से बल्लेबाजी में काफी उम्मीदें होंगी। गेंदबाजी में कप्तान राशिद खान और फजलहक फारूकी अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोनों देशों के बीच साल 2014 से अब तक कुल 12 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें 7 मैच अफगानिस्तान ने जीते। बांग्लादेश की टीम 5 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है। आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम की पिच ने एशिया कप में अब तक बल्लेबाजों को मदद की है, लेकिन गेंदबाज भी इससे फायदा उठाते नजर आए हैं। मंगलवार को आबू धाबी में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

अफगानिस्तान की टीम

सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारुकी, फरीद अहमद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, दरवेश रसूली और शराफुद्दीन अशरफ।

बांग्लादेश की टीम

तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, लिटन दास(कप्तान/विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, मेहदी हसन, जेकर अली, शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, सैफ हसन, नसुम अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन, तस्कीन अहमद और नुरुल हसन।

इंडियन बैंक ने जीता फर्स्ट चैलेंज कप फिर मिलने के वादे के साथ राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन

जोधपुर, एजेंसी। जोधपुर में प्रथम चैलेंज कप बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उच्च स्तरीय मुकाबले देखने को मिले। विविध राज्यों के खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ खेले। हर मैच के साथ जोधपुरवासियों को रोमांच देखने को मिला। केन्द्रीय संस्कृति एवम् पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के मुख्य आथित्य में आयोजित फाइनल मैच पुरूष वर्ग में इंडियन बैंक की टीम विजेता रही। महिला वर्ग में नॉर्दन रेलवे वूमेन टीम विजेता रही। एम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों का हुजूम उमड़ा।

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बास्केट बॉल संघ जोधपुर का अध्यक्ष होने के नाते विविध राज्यों से आए खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का स्वागत किया।

केन्द्रीय मंत्री शेखावत पूरे मैच में मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय के आईजी एम एल गर्ग, जोधपुर एम्स के निदेशक डॉ गोवर्धन दत्त पुरी, जोधपुर बास्केट बॉल संघ के सचिव देवेन्द्र सिंह चौहान , सचिव राजस्थान संघ देवेन्द्र सिंह शेखावत, ओलंपियन एवं अर्जुन अवॉर्डी हनुमान सिंह राठौड़ सहित अनेक गणमान्य लोग और भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी फाइनल मैच में मौजूद रहे। प्रतियोगिता में पुरूष वर्ग का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इसमें इंडियन बैंक की टीम ने यंग ओरियंस को मात देकर प्रथम चैलेंज कप पर कब्जा जमाया। इंडियन बैंक की टीम सिर्फ दो प्वाइंट के अन्तर से ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। दोनों ही टीमों ने एक एक प्वाइंट के लिए संघर्ष किया। अन्तिम सैकंड में इंडियन बैंक की टीम जीतने में सफल रही। इंडियन बैंक ने संघर्षपूर्ण मैच के अंतिम समय में 74 72 अंकों से पराजित कर पुरुष वर्ग का खिताब जीता । जिला बास्केट बॉल संघ जोधपुर के अध्यक्ष एवं केन्द्रीय संस्कृति एवम् पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने समापन समारोह में विजेता उप विजेता टीमों और विविध वर्गों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रतिभागी टीमों को स्मृति चिह्न नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस आयोजन को कड़ी मेहनत से सफलता के इस सोपान तक पहुंचाने वाले जोधपुर बास्केट बॉल संघ की पूरी टीम और सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। सचिव देवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि जिला बास्केटबॉल संघ जोधपुर के तत्वाधान में एम्स स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में आयोजित फर्स्ट चैलेंज कप बास्केटबॉल प्रतियोगिता मे पुरुष वर्ग के फाइनल मैच में विजेता इंडियन बैंक को ?300000 एवं उपविजेता टीम को ?200000 का पुरस्कार दिया गया। सेमीफाइनल में पहुंची अन्य दो टीमों भारतीय सेना एवं मध्य प्रदेश टीम को ?30 30 हजार , अन्य भाग लेने वाली टीमों को ?20000 की इनामी राशि प्रदान की गई। महिला वर्ग के फाइनल मैच में उत्तर रेलवे ने मेजबान जोधपुर टीम को 67 46 अंकों से पराजित कर खिताब जीता ।

एशिया कप से रैफरी को हटाने की पाकिस्तानी मांग खारिज

टीम इंडिया ने PAK खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, PCB ने रेफरी को जिमेदार बताया

दुबई,एजेंसी। भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय टीम ने यह फैसला अचानक नहीं लिया। इसमें BCCI और सरकार दोनों की सहमति थी कि मैच तो खेलेंगे, लेकिन दोस्ताना माहौल नहीं दिखेगा। रविवार को खेले गए इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था।पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नो हैंडशेक मामले की शिकायत ICC से की थी और मैच रेफरी को हटाने की मांग की है। ICC ने इस मांग को खारिज कर दिया है।

पूरे टूर्नामेंट में हाथ नहीं मिलाएगी टीम इंडिया: पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का यह सिलसिला पूरे टूर्नामेंट में जारी रहेगा। खिलाड़ियों, BCCI और सरकार के बीच इस पर आपसी सहमति है। BCCI की ओर से ऑफिशियल रिएक्शन अभी नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर भारतीय टीम 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में पहुंचती है और जीतती है, तो वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी। नकवी इस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष भी हैं।

भारत-पाकिस्तान 21 सितंबर को फिर भिड़ सकते हैं: 21 सितंबर को दोनों टीमें सुपर-4 राउंड में दोबारा आमने-सामने हो सकती हैं और वहां भी भारत का यही रुख रहेगा। हालांकि, इसके लिए पाकिस्तान को यूएई को हराना होगा।**पाकिस्तान ने रेफरी को हाथ न मिलाने का जिम्मेदार बताया:** भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर पाकिस्तान ने इसकी शिकायत मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट से की। आरोप लगाया कि भारतीय टीम ने खेल भावना नहीं दिखाई। PCB का आरोप है कि रेफरी ने टॉस के बाद दोनों कप्तानों को हाथ न मिलाने के लिए कहा था और यह भारतीय टीम के दबाव में किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सोमवार को कहा- PCB ने पायक्रॉफ्ट को तत्काल बाहर करने की मांग की है। उन्होंने ICC कोड ऑफ कंडक्ट और क्रिकेट के स्पिरिट का पालन नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं होने पर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है।

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी विवाद में कूदे: इस हैंडशेक कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर भी कूद गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा- अगर पहलगाम की ही बात है तो भारत हमसे जंग लड़ ले। क्रिकेट में इन बातों को मत लाओ। वहीं, पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि भारतीय टीम ने मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन, यह सिर्फ क्रिकेट मैच था। इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा- क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दें, इसमें सियासत न करें। **सूर्या ने कहा था- कुछ बातें खेल भावना से ऊपर होती हैं:** मैच के बाद हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा - कुछ बातें खेल भावना से ऊपर होती हैं। टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला BCCI और भारत सरकार की सहमति से लिया था। भारतीय टीम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़ी है और यह जीत भारतीय सैन्य बल को समर्पित है। बीते 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थक आतंकियों ने 26 भारतीयों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। साथ ही पाकिस्तान के नौ एयरबेस भी उड़ा दिए थे।

क्या कहते हैं ICC Øæ ACC के नियम: क्रिकेट के किसी भी रूल बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि मैच के बाद हैंडशेक करना जरूरी है। हाथ मिलाना कोई नियम नहीं है, बल्कि इसे खेल भावना का हिस्सा माना जाता है। यही कारण है कि लगभग हर मैच के बाद दोनों टीम के खिलाड़ी एक-दूसरे मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, 'नियमों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको विरोधी टीम से हाथ मिलाना ही होगा। भारतीय टीम ऐसे देश से हाथ मिलाने के लिए बाध्य नहीं है, जिससे रिश्ते इतने खराब हों।'

शिकायत में देरी के लिए PCB डायरेक्टर सस्पेंड: शिकायत में देरी के लिए PCB ने अपने डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस उस्मान वहाला को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाला को टॉस के वक्त ही शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी।

पीकेएल-12 : पांच सुपर टैकल के दम पर हरियाणा स्टीलर्स ने गुजरात जाएंट्स को 3 अंक से हराया

जयपुर, एजेंसी। मौजूदा चैंपियन हरियाणा स्टीलर्स ने पांच सुपर टैकल के दम पर सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में सोमवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के 33वें मुकाबले में गुजरात जाएंट्स को 40-37 से हरा दिया। हरियाणा की पांच मैचों में यह तीसरी जीत है जबकि गुजरात को छह मैचों में पांचवीं हार मिली है।

हरियाणा की जीत में शिवम पटारे (12) के अलावा डिफेंस मे कप्तान जयदीप (6) और राहुल सेतपाल (3) ने शानदार खेल दिखाया। विनय ने भी 8 अंक लेकर एचएस राकेश (14) और हिमांशु सिंह (6) के शानदार प्रदर्शन को फीका कर दिया।

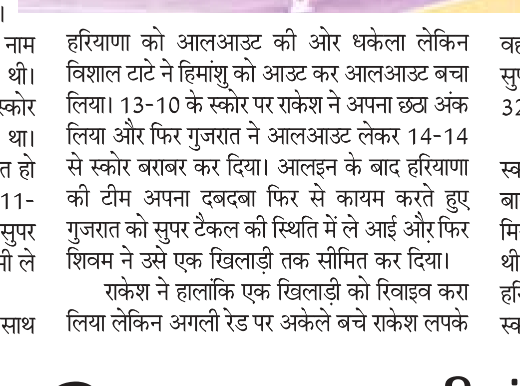

शुरुआती 10 मिनट पूरी तरह हरियाणा के नाम रहे। एक समय यह टीम 1-4 से पीछे चल रही थी। उसके लिए सुपर टैकल आन था। फिर 4-6 के स्कोर पर एक बार फिर उसके लिए सुपर टैकल आन था। एक समय तो हरियाणा दो खिलाड़ियों तक सीमित हो गए थे। यहां से हरियाणा ने जो रफ्तार पकड़ी वह 11-8 की लीड पर ही समाप्त हुई। हरियाणा ने तीन सुपर टैकल के साथ न सिर्फ वापसी की बल्कि लीड भी ले ली।

ब्रेक के बाद हिमांशु ने दो अंक की रेड के साथ हरियाणा को आलआउट की ओर धकेला लेकिन विशाल टाटे ने हिमांशु को आउट कर आलआउट बचा लिया। 13-10 के स्कोर पर राकेश ने अपना छठा अंक लिया और फिर गुजरात ने आलआउट लेकर 14-14 से स्कोर बराबर कर दिया। आलइन के बाद हरियाणा की टीम अपना दबदबा फिर से कायम करते हुए गुजरात को सुपर टैकल की स्थिति में ले आई और फिर शिवम ने उसे एक खिलाड़ी तक सीमित कर दिया।

राकेश ने हालांकि एक खिलाड़ी को रिवाइव करा लिया लेकिन अगली रेड पर अकेले बचे राकेश लपके गए और इस तरह हरियाणा ने हाफटाइम तक 25-20 की लीड ले ली। हाफटाइम के बाद राकेश ने सुपर-10 पूरा किया। राकेश हालांकि अगली रेड पर लपके गए और फिर शिवम ने लगातार दो अंक लेकर फासला 6 का कर दिया। इस बीच शिवम को लपक गुजरात ने शादलू को रिवाइव करा लिया। बीते पांच मिनट में गुजरात ने 3 के मुकाबले 5 अंक लेकर वापसी की राह पकड़ ली थी। फिर विनय को लपक गुजरात ने हरियाणा को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। हालांकि सेतपाल ने राकेश को सुपर टैकल कर इस स्थिति को टाल दिया। मयंक को लपक नितिन ने फिर वही स्थिति बहाल कर दी लेकिन जयदीप ने पांचवें सुपर टैकल के साथ 30 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 32-27 कर दिया। जयदीप का हाई-5 पूरा हुआ।

ब्रेक के बाद गुजरात ने लगातार दो अंक लेकर स्कोर 29-32 कर और फिर राकेश की बदौलत दूसरी बार आलआउट लेकर स्कोर 33-33 कर दिया। 35 मिनट बाद हरियाणा को एक अंक की लीड मिली हुई थी। इस बीच डू ओर डाई रेड पर मयंक को लपक हरियाणा ने लीड 3 की कर ली। फिर राकेश को लपक स्कोर 38-34 कर दिया।

लगातार दूसरी बार वैशाली ने जीता फिडे ग्रैंड स्विस खिताब

पीएम मोदी ने ऐतिहासिक उपलब्धि को सराहा

नई दिल्ली, एजेंसी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेशबाबू को लगातार दूसरी बार फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीतकर इतिहास रचने के लिए बधाई दी है। उन्होंने इसे उत्कृष्ट उपलब्धि बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्कृष्ट उपलब्धि। वैशाली रमेशबाबू को बधाई। उनका जुनून और समर्पण अनुकरणीय है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।

वैशाली रमेशबाबू ने सोमवार को पूर्व महिला विश्व चैंपियन टैन झोंग्यी को अंतिम दौर में ड्रॉ पर रोककर टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए जीत सुनिश्चित की।

वैशाली और कैटरिना लैग्नो दोनों ने 8 अंक हासिल किए थे, लेकिन वैशाली को टाईब्रेक स्कोर में बढ़त मिली थी, जिसके चलते उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। यह उनकी दूसरी ग्रैंड स्विस जीत है।

इसी के साथ ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेशबाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

वैशाली रमेशबाबू को इस जीत पर वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने भी बधाई दी है। आनंद ने एक्स पोस्ट में लिखा, वैशाली रमेशबाबू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। उनकी दृढ़ता और कड़ी मेहनत वास्तव में प्रशंसनीय है। फिडे ग्रैंड स्विस को दो बार जीतना एक ऐसी उपलब्धि है, जो कुछ ही लोग हासिल कर सकते हैं। इस जीत के साथ वैशाली रमेशबाबू ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली, जो विश्व चैंपियनशिप के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का आयोजन साल 2026 में होगा।

भारत अब महिला वर्ग में तीन प्रतिभागियों को उतारेगा। इनमें वैशाली, कोनेरू हम्पी और विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख शामिल हैं।

इस प्रतियोगिता में शामिल अन्य भारतीयों में से कोई भी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह नहीं बना सका। वहीं, नीदरलैंड के अनीश गिरी ओपन वर्ग में विजेता रहे, जिन्होंने अमेरिका के हैंस मोके नीमन को शिकस्त दी।

स्मृति मंधाना आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर बनीं नंबर वन

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत की स्टार बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को खेले गए पहले वनडे में मंधाना ने 63 गेंदों पर 58 रन बनाए थे, जिसकी बदौलत उन्होंने इंग्लैंड की कप्तान नैट स्किवर-ब्रंट को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 पोजीशन हासिल की। यह चौथी बार है जब मंधाना ने वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में नंबर-1 स्थान पाया है। उन्होंने जनवरी 2019 में पहली बार यह उपलब्धि हासिल की थी और जुलाई 2025 में भी वह नंबर-1 बनी थीं, लेकिन बाद में स्किवर-ब्रंट ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर 12वें और जेमिमा रोड्रिग्स 15वें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी तीन स्थान

ऊपर चढ़कर पांचवें नंबर पर पहुंच गई हैं, जबकि एनाबेल सदरलैंड और फोबे लिचफील्ड संयुक्त रूप से 25वें स्थान पर हैं। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का 282 रन का लक्ष्य आठ विकेट और 35 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया था। तीन मैचों की सीरीज़ का दूसरा वनडे बुधवार को खेला जाएगा। गेंदबाज़ी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की किम गार्थ चौथे और अलाना किंग पांचवें स्थान पर पहुंचकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर हैं।

बीएस जामोद ने संभागीय बैठक में उच्च कार्यालयों से संबंधित प्रकरणों में भी प्रयास कर निराकरण करानें के निर्देश दिए

स्वच्छता ही सेवा सप्ताह की हर गतिविधि प्रभावी रूप से करें : कमिश्नर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने संभागीय बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं की विभागवार समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि संभागीय बैठक के जो बिन्दु वरिष्ठ कार्यालयों में कार्यवाही के लिए भेजे गए हैं उनमें भी लगातार प्रयास करके निराकरण कराएं। शासन स्तर पर प्रस्तावित किए गए कार्यों की स्वीकृति जारी कराकर उसे अमलीजामा पहनाएं। मैहर में आद्योगिक केन्द्र की स्थापना तथा सिंगरौली में स्टेडियम निर्माण के संबंध में रिपोर्ट दो दिवस में प्रस्तुत करें। जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग मऊगंज कलेक्टर से संपर्क करके मऊगंज में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा छात्रावास भवन निर्माण के लिए जमीन आवंटित कराएं। सतना जिले में दौरी सागर बांध निर्माण के लिए भू अर्जन के प्रकरण तथा सीतापुर-हनुमना उद्वहन सिंचाई

परियोजना की प्रस्तावित कार्ययोजना समय पर प्रस्तुत करें।

कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी विभागीय कार्यों की निगरानी के लिए क्षेत्र का भ्रमण करें। भ्रमण के समय स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र तथा छात्रावासों का निरीक्षण करके उनकी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में रिपोर्ट दें। सीएम हेल्पलाइन में 100 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। सितम्बर माह के प्रकरणों का निराकरण करके विभाग की ग्रेडिंग में सुधार करें। राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग, पीएचई, स्वास्थ्य विभाग तथा गृह विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। संबंधित अधिकारी इनके निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें।

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मध्यप्रदेश में धार जिले से अभियान का 17 सितम्बर को शुभारंभ करेंगे। इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक गर्भवती महिला का पंजीयन और जाँच के लिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मैदानी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर प्रत्येक महिला को निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच का लाभ दें। अभियान के दौरान 21 सितम्बर को सुबह 7 बजे नमो मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दो हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। संभागीय खेल अधिकारी अन्य विभागों के सहयोग से इसके लिए आवश्यक प्रबंध करें। पखवाड़े में 25 सितम्बर को एक घण्टे स्वच्छता के लिए तथा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी दिन महिला स्वसहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर तक पोषण माह मना रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविरों में पोषण आहार की प्रदर्शनी लगाएं।

कमिश्नर ने कहा कि उच्च शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा विभाग स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में विकसित भारत की थीम पर चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करे। पखवाड़े में नगरीय निकायों तथा सभी ग्राम पंचायतों में प्रमुख धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई का अभियान चलाएं। अधीक्षण यंत्री पीएचई सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्र और छात्रावासों में नलजल योजनाओं से नल कनेक्शन कराएं। वर्तमान में ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर नलजल योजनाओं का इसी अवधि में सत्यापन कराकर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त करें। बैठक में कमिश्नर ने ई आफिस व्यवस्था, पेंशन प्रकरणों के निराकरण तथा छात्रावासों के निरीक्षण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त बीएल अहिरवार, डीन मेडिकल कालेज डॉ सुनील अग्रवाल, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग एसके तिवारी, अधीक्षण यंत्री पीएचई महेन्द्र सिंह तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

गंभीर बनती जा रही आवारा पशुओं की समस्या : अविराज

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण लोग आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जिससे शहर तथा जिले में भय का माहौल व्याप्त है। प्रशासन की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ती जा रही है। युवा नेता अविराज ने एक विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया है कि जिले और शहर में आवारा पशुओं की समस्या गंभीर बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन केवल कार्यवाही की बात करता है, लेकिन हकीकत सड़कों पर देखने को मिल रही है। आवारा पशुओं की वजह से लोग चोटिल और गंभीर हादसों का शिकार हो रहे हैं। ये पशु दिन-रात मुख्य सड़कों और रिहायशी इलाकों में घूमते रहते हैं, जिससे हर वक्त हादसों का खतरा बना रहता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवारा पशुओं से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। रात के समय ये पशु खेतों में घुसकर फसले नष्ट कर रहे हैं, जिससे किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

अविराज ने प्रशासन से आवारा पशुओं की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे रणनीति बनाकर आंदोलन करेंगे।

कमिश्नर और अन्य अधिकारी साइकिल से पहुंचे कार्यालय

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। पर्यावरण की सुरक्षा तथा स्वयं की स्वास्थ्य रक्षा रक्षा के उद्देश्य से सप्ताह में मंगलवार के दिन कमिश्नर बीएस जामोद की पहल पर अधिकारी और कर्मचारी साइकिल से कार्यालय पहुंच रहे हैं। यह क्रम लगातार बना हुआ है। सुमंगल साइकिल दिवस पर कमिश्नर और अन्य अधिकारी साइकिल से कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। कमिश्नर के साथ संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, उप संचालक खनिज बसंतराम, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ आरपी सिंह, संयुक्त संचालक सामाजिक

न्याय अनिल दुबे, संयुक्त संचालक पेंशन टीएन टेकाम तथा कमिश्नर कार्यालय के कर्मचारी भी साइकिल से कार्यालय पहुंचे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने कार्यालय पहुंचने के लिए ई रिक्शा का उपयोग किया।

तालाब योजना में रोजगार सहायक ने 8 लाख गबन किया, लोगों ने जन सुनवाई में कलेक्टर से की शिकायत; कहा- जांच की जाए

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने 32 आवेदनों पर सुनवाई की। जनसुनवाई में सबसे गंभीर मामला बेलहई खुर्द का सामने आया। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक विनय कुमार पाण्डेय पर खेत तालाब योजना में 7-8 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया। ग्रामीणों के अनुसार 2020 में स्वीकृत तालाब निर्माण कार्य बिना सूचना के रोक दिया गया। मई-जून 2025 में फर्जी मास्टर रोल बनाकर राशि निकाल ली गई।

लोगों ने की जांच की

मांग: चित्रभान सिंह, रामपाल सिंह, राजपाल सिंह, कृष्णपाल सिंह, शिवकुमार पाण्डेय, विजय शंकर पाण्डेय और उपकार पाठक ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने शीघ्र कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

इन समस्याओं को लेकर पहुंचे लोग: जनसुनवाई में अन्य विषयों पर भी आवेदन आए। इनमें अतिथि शिक्षक की अवैध नियुक्ति, भूमि कब्जा, खसरे में नाम दर्ज कराने, घर गिरने और लाड़ली बहना योजना में नाम जुड़वाने के मामले शामिल थे। प्रियंका पटेल ने आंगनवाड़ी ज्वाइनिंग के लिए और पूनम पटेल ने अतिथि पद पर अवैध नियुक्ति की शिकायत दर्ज कराई।

कलेक्टर ने सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेज दिया है। उन्होंने अधिकारियों को 7 दिन के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवेदकों को की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर पी.के. पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर ए.पी. द्विवेदी और रश्मि चतुर्वेदी उपस्थित रहे।

कृत्रिम अंग के लिए वरिष्ठजनों की जाँच के लिए लगेंगे शिविर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा जिले के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक कृत्रिम उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उपकरणों का निर्माण भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम तथा एलिम्को संस्था द्वारा किया जाएगा। कृत्रिम अंग के लिए पात्र दिव्यांगों का चिन्हांकन कराने के लिए जिले भर में शिविर लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि 29 सितम्बर को विधि महाविद्यालय रीवा में शिविर लगाया जाएगा। इसमें जनपद पंचायत रीवा, जनपद पंचायत सिरमौर, नगर निगम रीवा, नगर परिषद गोविंदगढ़, नगर परिषद सिरमौर, नगर परिषद सेमरिया तथा नगर परिषद बैकुण्ठपुर के वरिष्ठजनों की जाँच की जाएगी।

रायपुर कर्चुलियान जनपद पंचायत सभागार में 30 सितम्बर को आयोजित शिविर में जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान तथा गंगेव एवं नगर परिषद मनगवां तथा गुढ़ के हितग्राहियों की जाँच होगी। जनपद सभागार त्योंथर में 3 अक्टूबर को आयोजित शिविर में जनपद पंचायत त्योंथर तथा जवा एवं नगर परिषद त्योंथर, चाकघाट एवं डभौरा के हितग्राहियों की जाँच की जाएगी। जाँच में कृत्रिम अंग के लिए पात्र पाए गए बुजुर्गों को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सभी पात्र बुजुर्गों को शिविर में उपस्थित कराकर जाँच कराने के निर्देश दिए हैं।

गणेश विसर्जन के दिन युवक की मौत, एसपी से मिल परिजन ने हत्या की आशंका जताई; दोस्तों पर लगाए आरोप

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दिन युवक रामदयाल कुशवाहा की एक्सीडेंट में मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और घटना की गंभीरता बताते हुए कार्रवाई की मांग की।

परिजनों के मुताबिक, रामदयाल कुशवाहा पिता रामेश्वर प्रसाद कुशवाहा, निवासी शिवपुरवा, शाम को गणेश विसर्जन में जाने के लिए निकले थे। रात तक वह घर नहीं लौटे और फोन के माध्यम से पता चला कि उनका बेटा एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। बाद में रामदयाल मृत अवस्था में मिला।

परिवार ने दोस्तों की

हरकतें संदिग्ध बताई: मृतक के पिता ने बताया कि रामदयाल के दोस्तों की हरकतें शुरू से संदिग्ध थीं। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। बेटे का उसके एक दोस्त से विवाद भी हुआ था। अगर घटना की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए तो महत्वपूर्ण बिंदु सामने आ सकते हैं और बेटे को न्याय मिल सकता है।

एसपी ने मामले की जांच शुरू की: रीवा एसपी ने परिजनों की शिकायत पर मामले को जांच में लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच कर रही है।

कलेक्टर ने 35 आवेदन पत्रों में की सुनवाई

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। आमजनता के आवेदनों पर कार्यवाही के लिए कलेक्ट्रेट सभागार मऊगंज में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कलेक्टर संजय कुमार जैन ने आमजनता के 35 आवेदनों में सुनवाई की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी आमजनता के आवेदन पत्रों में संवेदनशीलता और तत्परता से कार्यवाही करके सात दिवस में निराकरण करें। आवेदक को भी आवेदन पत्र में की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर पीके पाण्डेय तथा संयुक्त कलेक्टर एपी द्विवेदी ने भी आमजनता के आवेदनों में सुनवाई की। जनसुनवाई में प्रियंका पटेल निवासी रजिगवां ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के संबंध में आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। पूनम पटेल निवासी मऊगंज ने अतिथि शिक्षक पद पर नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र में जाँच कर कार्यवाही के निर्देश दिए। जयकृष्ण चौरसिया निवासी मऊगंज ने शासकीय मार्ग से अवैध कब्जा हटाने के लिए

आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार मऊगंज को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। अविनाश तिवारी तथा सुरसरी त्रिपाठी निवासी ग्राम खुझवा ने वर्षा से घर गिर जाने पर आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार मऊगंज को मौके पर जाकर जाँच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जमीन के सीमांकन, खसरे में नाम दर्ज करने, लाड़ली बहना योजना में नाम जुड़वाने तथा शक्तिचलित तिपहिया साइकिल प्रदान करने संबंधी आवेदनों में सुनवाई की गई।

रोजगार मेला 18 सितंबर को संभागीय आईटीआई रीवा में

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। युवा संगम कार्यक्रम के तहत संभागीय आईटीआई रीवा में 18 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोजगार मेला आयोजित किया जायेगा। रोजगार मेले में जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में 31 कंपनियों द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा। मेले में शामिल होने के लिए विभिन्न कंपनियों में युवक एवं युवतियों की आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। वेतन एवं भत्ते 7000 रुपए से 35 हजार रुपए तक निर्धारित किया गया है। वेतन एवं भत्ता विभिन्न कंपनियों में अलग-अलग देय होगा। युवाओ को अपने साथ मूल अंकसूची तथा निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड या वोटर आईडी, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन एवं नवीनतम दो पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर आना अनिवार्य होगा।

उप संचालक ने बताया कि रोजगार मेले में जीएमसीसी मीडिया इंडिया प्रा.लि. पुणे महाराष्ट्र, फुलम्ब्राी टेक्स्ट कॉम प्रा. लि. सानन्द गुजरात, ट्रायडेन्ट कम्पनी बुधनी सिहोर, डी एण्ड एच सेचरोन कंपनी इंदौर (आईसेक्ट), विनप्रेज इन्फो मीडिया प्रा.लि. मैहर, यशस्वी ग्रुप भोपाल, प्रगतिशील बायोटेक प्रा.लि. रीवा, बजाज ऑटो लिमि. पुणे महाराष्ट्र, आमधनी प्रा. लि. (अपोलो टायर्स) गुजरात, फुरूकावा मिंडा इलेक्ट्रिक प्रा.लि. हरियाणा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज रेणुकुट सोनभद्र यूपी, प्रभा बायोप्लांट्स प्रा. लि. रीवा, मिग्मा पैकट्रॉन प्रा. लि. रीवा, प्रगतिशील एग्रोटेक प्रा.लि.रीवा, एच.डी.एफ.सी. लाईफ इश्योरेन्स कम्पनी लिमि. रीवा, प्रगतिशील बॉयोटेक प्रा.लि. सवेरा सतना, स्वतंत्र माइक्रोफिन प्रा.लि. भोपाल, प्रतिभा सिन्टेक्स लि. पीथमपुर धार तथा टैलेंटकॉर्प सॉल्यूशंस प्रा. लि. चाकन में रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे।

जनसुनवाई में करारी बस्ती निवासियों ने अवरूद्ध मार्ग की बाधा को दूर करने का दिया आवेदन

जनसुनवाई में 68 आवेदकों की सुनी गई समस्यायें

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के संबंध में प्राप्त आवेदनों को विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। डिप्टी कलेक्टर एस.के. बेक ने आवेदकों की समस्यायें सुनीं। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित जनसुनवाई में करारी बस्ती के निवासियों के अवरूद्ध मार्ग को प्रारंभ करने का आवेदन दिया जिस पर एसडीएम मनगवां को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। चाकघाट निवासी रामकृपाल मिश्रा के रास्ते से अतिक्रमण हटाने का आवेदन पर तहसीलदार त्योंथर को, लोही निवासी चन्द्रवती ओझा

के नहर से मिट्टी कटने पर फसल क्षतिग्रस्त होने पर सहायता राशि प्रदान करने के आवेदन पर तहसीलदार गुढ़ को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। इसी प्रकार राम निवास पटेल नौढ़िया के खसरा सुधार के आवेदन एवं लालमणि तिवारी लोही के मुआवजा राशि प्रदान करने के आवेदन को संबंधित एसडीएम को कार्यवाही के लिये प्रेषित किया गया।

जनसुनवाई में मीनू मिश्रा निवासी कस्तरा के साइकिल प्रदान करने के आवेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी को, रामकिशोर आदिवासी बराकोठार के रास्ता निर्माण के आवेदन को सीईओ जनपद रीवा को, मनोज कुमार सिंह निवासी खम्हरिया के ग्रामीण विकास कार्यों की जांच के आवेदन को सीईओ जवा को कार्यवाही के लिये प्रेषित किया गया। जबकि करहिया नंबर एक निवासी ललित साकेत के बिजली बिल सुधार के आवेदन पर एमपीईबी को, नौबस्ता निवासी मनधीर प्रसाद पाण्डेय के प्रधानमंत्री आवास की राशि प्रदाय किये जाने के आवेदन को सीईओ जनपद त्योंथर को, कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। दादर निवासी रिंकी कोरी के अर्न्तजातीय विभाग की प्रोत्साहन राशि दिलाये जाने के आवेदन पर जिला संयोजक जनजातीय कार्य को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

मऊगंज में वरिष्ठजनों की जाँच के लिए शिविर एक अक्टूबर को

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा बुजुर्गों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए जाँच शिविर लगाए जा रहे हैं। मऊगंज जिले में जनपद पंचायत मऊगंज के सभागार में एक अक्टूबर को शिविर लगाया जा रहा है। इसमें जनपद पंचायत नईगढ़ी, हनुमना तथा मऊगंज एवं नगर परिषद नईगढ़ी, हनुमना एवं मऊगंज के हितग्राहियों की जाँच की जाएगी। इनमें कृत्रिम अंग के लिए पात्र पाए गए बुजुर्गों को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम तथा एलिम्को संस्था द्वारा निःशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे। कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मऊगंज को शिविर के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक/प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया ऑडीटर पब्लिकेशन प्रा.लिमि. राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से प्रकाशित, **संपादक संदीप द्विवेदी**, आर.एन.आई नं. 69082/97, डाक पंजीयन क्र.- म. प्र./ रीवा संभाग/ 46/2023-2025, प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9589645803, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।